राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई,उतरप्रदेश,बिहार,राजस्थान,मध्यप्रदेश,उतरांचल,उतराखंड,दिल्ली,हरियाणा में प्रसारीत

क्रांति समय
SURESH MAURYA
(Chief Editor)
M. 98791 41480
Working. off.: STPI-SURAT, GUJARAT-395023
(Software Technology Park of India, Surat.
www.krantisamay.com
www.krantisamay.in
krantisamay@gmail.com

सुरत–गुजरात,संस्करण बुधवार11नवम्बर2020 वर्ष–3, अंक–286 पृष्ठ–08– मूल्य–01–रूपया

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

LAC पर तनाव के बीच पहली बार SCO की बैठक में आमने-सामने होंगे मोदी और शी जिनपिंग, इमरान खान भी शामिल

नई दिल्ली। वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर महीनों से जारी तनाव के बीच पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक मंच पर होंगे। दरअसल दोनों नेता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के राष्ट्रध्यक्षों की 20वीं बैठक में शिरकत करेंगे। इसमें पाकिस्तानी पीएम इमरान खान भी भाग लेंगे। शंघाई सहयोग सम्मेलन की यह तीसरी मीटिंग है जिसमें भारत पूर्ण सदस्य के रूप में भाग ले रहा है। गौरतलब है कि गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद दोनों देशों में विवाद चरम पर है। जिसके बाद भारत-चीन की कई दौर की विफल सैन्य और कूटनीतिक वार्ताओं के बीच यह बैठक अहम मानी जा रही है। विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्व ने इस वर्चुअल समिट के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। श्रीवास्तव ने कहा, 'प्रधानमंत्री एससीओ के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद के 20वें शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे जो 10 नवंबर को ऑनलाइन आयोजित होगा। बैठक की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन करेंगे।' बता दें कि भारत, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान हैं। ईरान, अफगानिस्तान, बेलारूस, रूस, चीन, पाकिस्तान, कजाकस्तान, किर्गिजस्तान और मंगोलिया ऑब्जर्वर के रूप में संगठन से जुड़े हैं। वहीं, अर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की डॉयलॉग पार्टनर के रूप में एससीओ के सदस्य हैं। इस बैठक में सभी सदस्य देश सुरक्षा, आतंकरोधी कार्रवाई, आर्थिक, मानवीय सहयोग महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। यहां अफगानिस्तान और मध्य-पूर्व की स्थिति पर खास फोकस रहेगा।

महाराष्ट्र, झारखंड के बाद पंजाब सरकार ने भी CBI से जनरल कंसेंट लिया वापस, हर केस में लेनी होगी इजाजत

चंडीगढ़। महाराष्ट्र और झारखंड के बाद पंजाब सरकार ने भी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) से जनरल कंसेंट यानी सामान्य सहमित को वापस ले लिया है। इसका मतलब यह है कि अब बिना इजाजत सीबीआई पंजाब में किसी भी नए मामले की जांच नहीं कर सकेगी और उसे हर केस के लिए राज्य सरकार से मंजूरी लेनी होगी। हाल ही में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने भी सीबीआई से सामान्य सहमति वापस ले ली थी। इसी महीने झारखंड सरकार ने भी सीबीआई से यह सहमति वापस लेने की घोषणा की है।

सामान्य सहमति क्या है?

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के विपरीत, जो अपने स्वयं के एनआईए अधिनियम द्वारा शासित होती है और जिसका देशभर में अधिकार क्षेत्र है, सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम द्वारा शासित की जाती है। यह अधिनियम उसे किसी भी राज्य में जांच के लिए एक राज्य सरकार की सहमति को अनिवार्य करता है।

दो तरह की होती हैं सहमति

कुल दो प्रकार की सहमति होती हैं। पहली केस स्पेसिफिक और दूसरी जनरल (सामान्य)। यूं तो सीबीआई का अधिकार क्षेत्र केंद्र सरकार के विभागों और कर्मचारियों पर है, लेकिन राज्य सरकार से जुड़े किसी मामले की जांच करने के लिए उसे राज्य सरकार की सहमति की जरूरत होती है। इसके बाद ही, वह राज्य में मामले की जांच कर सकती हे।

क्या सीबीआई अब महाराष्ट्र में कोई जांच नहीं कर पाएगी? सीबीआई ने जनरल कन्सेन्ट वापसी से पहले तक पंजाब में जो भी केस दर्ज किए हैं, उनकी जांच वह कर सकेगी। छापेमारी को लेकर स्थिति बहुत साफ नहीं है, लेकिन पुराने मामलों में रेड मारने के लिए कोर्ट से वॉरंट लिया जा सकता है। वैसे, सीबीआई दूसरे राज्यों में दर्ज केस के तार पंजाब से जुड़े हों तो उस सिलसिले में पंजाब में जांच कर सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2018 में छत्तीसगढ़ के एक मामले में आदेश दिया था, जिसके मुताबिक केस का तार दिल्ली से जुड़ा हो तो सीबीआई दिल्ली में केस दर्ज कर सकती है और फिर उस केस की जांच कहीं भी कर सकती है।

सामान्य सहमति के वापस लेने का क्या मतलब?-इसका सीधा मतलब है कि सीबीआई बिना केस स्पेसिफिक सहमति मिले इन राज्यों में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई नया मामला नहीं दर्ज कर पाएगी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, सीबीआई अधिकारी ने बताया कि सामान्य सहमति को वापस लेने का मतलब है कि राज्य सरकार की अनुमति के बिना इन राज्यों में प्रवेश करते ही किसी भी सीबीआई अफसर के पुलिस अधिकारी के रूप में मिले सभी अधिकार खत्म हो जाते हैं। यह पहली बार नहीं है जब किसी राज्य सरकार ने अपने यहां सीबीआई की जांच के लिए उसकी एंट्री को रोक दिया हो।

जम्मू-कश्मीर में अफसरों की कमी पूरी करेंगे केंद्रीय सेवा के अफसर, केंद्र सरकार के विभागों में पत्र भेजकर मांगे गए नाम

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में अफसरों की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र की विभिन्न सेवाओं से अफसरों को भेजा जा सकता है। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में पत्र भेजकर जम्मू-कश्मीर भेजने के लिए अफसरों को चिन्हित करने और उनकी इच्छा जानकर सहमति सहित अन्य प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। ग्रुप ए सेवा के अफसरों से विकल्प मांगे जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में एक ज्ञापन पत्र भेजकर कहा गया है कि यह अनुरोध किया जाता है कि केंद्रीय सिविल सेवा, यूपीएससी द्वारा आयोजित केंद्रीय सिविल परीक्षाओं के माध्यम से चयनित भारतीय रक्षा लेखा सेवा, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज सेवा,भारतीय रक्षा संपदा सेवा आदि के अफसरों से उनकी इच्छा जानकर उपयुक्त अफसरों की सूची तैयार करें। इच्छुक अफसरों के लिए दिशा-निर्देश के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में काम करने के लिए सहमति प्राप्त करने और कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी से अनापत्ति हासिल करने,विजिलेंस क्लियरेंस आदि प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। इसी तरह का पत्र भारतीय रेलवे अकाउंट सेवा, भारतीय रेलवे

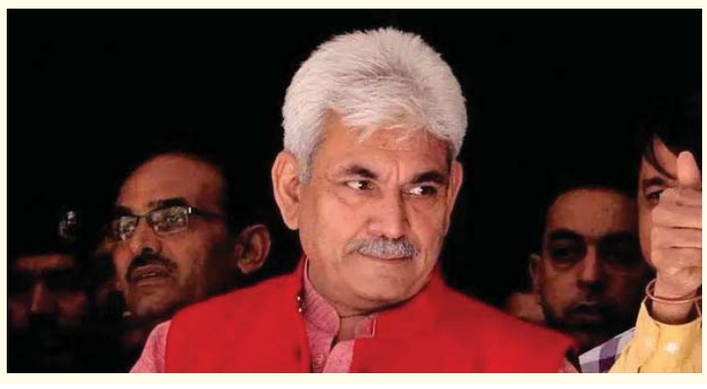

यह अनुरोध किया जाता है कि केंद्रीय सिविल सेवा, यूपीएससी द्वारा आयोजित केंद्रीय सिविल परीक्षाओं के माध्यम से चयनित भारतीय रक्षा लेखा सेवा, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज सेवा,भारतीय रक्षा संपदा सेवा आदि के अफसरों से उनकी इच्छा जानकर उपयुक्त अफसरों की सूची तैयार करें।

कार्मिक सेवा, भारतीय रेलवे यातायात सेवा और रेलवे सुरक्षा बल से संबंधित ग्रुप ए अफसरों की सहमति हासिल करने के लिए भेजा गया है। अविभाजित जम्मू-कश्मीर में लगभग चार लाख सरकारी कर्मचारी हैं। जम्मू-कश्मीर में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की कुल स्वीकृत छमता क्रमशः 137 और 147 पदों की है। इस समय 58 आईएएस और 66 आईपीएस अधिकारियों में से सभी केंद्रशासित प्रदेश में नहीं है। इनमें से कुछ केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं। जबकि कुछ निलंबित हैं। सूत्रों का कहना है कि रिटायरमेंट, प्रतिनियुक्ति और अन्य वजहों से कुल छमता में अफसर मौजूद नहीं रहते। सूत्रों ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में पहले से अफसरों की कमी है। साथ ही एक साल से ज्यादा का समय बीतने के बाद भी जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के बीच अधिकारियों के कैडर आवंटन की प्रक्रिया पूरी नही हो पाई है। ऐसे में विभिन्न केंद्रीय सेवाओ के जरिये कमी पूरी की जा सकती है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अनुसार, जम्मू और कश्मीर कैडर के आईएएस, आइपीएस और अन्य केंद्रीय सेवाओं के अफसर अपनी सेवाएं इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में यथावत जारी रखेंगे, लेकिन इन सेवाओं में जो नई भर्तियां होंगी।

भारतीय संविधान के तहत मिला है असहमति का अधिकार, इसकी होनी चाहिए पर्याप्त सुरक्षा

नई दिल्ली। आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद विवाद बढ़ता ही जा रहा है। एक और जहां इसे प्रेस की स्वतंत्रता पर बड़ा हमला बताया जा रहा है, वहीं अब इस मामले को लेकर पुलिस की पूरी कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं, क्योंकि यह केस दोबारा खोला गया है। पिछले साल 2019 में महाराष्ट्र पुलिस ने केस को यह कहते हुए बंद कर दिया था कि उन्हें पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। गौरतलब है कि पांच मई 2018 को एक इंटीरियर डिजानइर अन्वय नाईक ने महाराष्ट्र के अलीबाग में सुसाइड कर लिया था, उनकी मां भी घर में मृत पाई गई थीं। पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने इंटीरियर डिजाइनर के पैसों का भुगतान नहीं किया और उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर किया। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा है कि महत्वपूर्ण रिपोर्टिंग के खिलाफ राज्य शक्ति का उपयोग नहीं किया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना की तुलना आपातकाल से करते हुए इसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला बताया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पत्रकारों सहित कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार बदले की कार्रवाई के लिए कानून का बेजा इस्तेमाल नहीं कर सकती। एक पत्रकार के साथ पुलिस की इस तरह की कार्रवाई लोकतंत्र की आवाज का गला घोंटना है। बहुलता से बहुलवाद तक विषय पर व्याख्यान देते हुए लोकतंत्र में असहमति को सेफ्टी वाल्व बताया था। असहमति को राष्ट्र विरोधी और लोकतंत्र विरोधी करार देना संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण एवं विचार विमर्श करने वाले लोकतंत्र को बढ़ावा देने के प्रति देश की प्रतिबद्धता की मूल भावना पर चोट करती है। विचारों को दबाना देश की अंतरआत्मा को दबाना है।

मप्र में भाजपा की जीत के पीछे सत्ता और संगठन का समन्वय

भोपाल।

मध्य प्रदेश में आगामी तीन साल तक भाजपा की सरकार रहने वाली है क्योंकि उपचुनाव में उसने बड़ी जीत हासिल की है। भाजपा की इस जीत को सत्ता और संगठन के समन्वय की जीत माना जा रहा है।

राज्य में 28 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए और भाजपा के खाते में कम से कम 19 सीटों का आना तय है और यह जीत भाजपा की सरकार को स्थायित्व देने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा को पूर्ण बहुमत के लिए सिर्फ आठ सीटों की जरूरत थी और उसे इससे कहीं ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं। भाजपा के चुनाव प्रचार अभियान पर गौर करें तो एक बात साफ हो जाती है कि एक तरफ जहां संगठन प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत के नेतृत्व में मतदान केंद्र तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय बनाने की रणनीति पर काम कर रही थी तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रचार की कमान संभाले हुए थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा मुख्यमंत्री चौहान और पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंधिया तीन ऐसे चेहरे थे जिन पर प्रचार की पूरी कमान थी और उन्होंने राज्य की सभी 28 सीटों पर पहुंचकर पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। एक तरफ जहां प्रमुख नेताओं को पार्टी ने सक्रिय किया था तो वहीं संगठन से जुड़े पदाधिकारियों को अलग-अलग विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी गई। इतना ही नहीं मंत्रियों को भी विधानसभा क्षेत्रों में तैनात किया गया था साथ ही उनसे यह भी कहा गया था कि जिस मंत्री के इलाके में पार्टी हारेगी उसे मंत्री पद तक खोना पड़ सकता है। इसी का नतीजा रहा कि मंत्रियों ने भी किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा ने एक रणनीति के तहत चुनाव लड़ा। सरकार जनहित के फैसले लेते हुए किसान, महिलाओं, आदिवासियों से लेकर अन्य हितग्राहियों के खाते में योजनाओं की रकम भेजती रही तो दूसरी ओर प्रचार का अभियान पूरी तेजी से चला।

भाजपा में टीम भावना का समन्वय नजर आया-सत्ता और संगठन के समन्वय ने कार्यकर्ताओं में भी जोश बनाए रखा परिणाम स्वरूप भाजपा को बड़ी जीत हासिल हुई है।

सीमा विवाद सुलझाने के लिए नौवें दौर की वार्ता में शामिल होंगे भारत और चीन

नई दिल्ली।

भारत और चीन के सैन्य प्रतिनिधियों की ओर से पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद सुलझाने के लिए इस सप्ताह नौवीं बार बातचीत किए जाने की संभावना है। दोनों देशों ने आगे के स्थानों (फॉरवर्ड एरिया) से अपने सैनिकों को हटाने के लिए आठवें दौर की बातचीत के दौरान विचारों का रचनात्मक आदान-प्रदान किया था। दोनों देशों के बीच आठ कोर कमांडर स्तर की वार्ता छह नवंबर को हुई थी। दोनों पक्ष दोनों देशों के नेताओं द्वारा संपन्न महत्वपूर्ण सहमति को लागू करने, सेना के संयम बनाए रखने और गलतफहमी से बचने पर सहमत हुए थे। इसके साथ दोनों पक्ष इस बार की वार्ता के आधार पर सैन्य और राजनयिक संपर्क रखकर अन्य समस्याओं का समाधान करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने पर भी सहमत हुए थे। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने पिछले रविवार को एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि दोनों पक्षों ने भारत-चीन सीमा क्षेत्रों के पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पास असहमति पर विचारों का एक स्पष्ट, गहन और रचनात्मक आदान-प्रदान किया। मंत्रालय ने यह भी कहा था कि दोनों देश, दोनों देशों के नेताओं द्वारा महत्वपूर्ण सहमति को ईमानदारी से लागू करने के लिए सहमत हैं और अपने सीमावर्ती सैनिकों को संयम बरतने और गलतफहमी और गलतफहमी से बचने के लिए सुनिश्चित करने पर सहमत हैं। 30 अगस्त को भारत ने रेचन ला, रेजांग ला, मुकर्पी और टेबलटॉप जैसे पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर महत्वपूर्ण पहाड़ी ऊंचाइयों पर अपनी पहुंच सुनिश्चित कर ली थी, जो तब तक मानव रहित जगह होती थी। भारत ने ब्लैकटॉप के पास भी कुछ तैनाती की है। चीन द्वारा भड़काऊ सैन्य कदम उठाने की कोशिश के बाद भारत की ओर से यह कदम उठाए गए हैं। भारत और चीन के बीच पिछले सात महीने से एलएसी पर गतिरोध कायम है। कई स्तरों के संवाद के बावजूद कोई सफलता नहीं मिली है और गतिरोध जारी है।

आलू-प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर ममता ने लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी. ममता ने यह चिट्ठी आलू और प्याज के बहते दामों को लेकर लिखी है. ममता ने अपनी 4 पन्नों की चिट्ठी में हाल ही में संसद से पास हुए कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर निशाना साधने की कोशिश भी की है। ममता ने अपनी चिट्ठी की शुरुआत करते हुए लिखा है कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने किसानों और आवश्यक वस्तुओं से संबंधित तीन कानून बनाए हैं . ममता ने आगे लिखा है कि हमने अपनी गंभीर चिंताओं को उठाया था कि इन अधिनियमों को बिना पर्याप्त विचार या चर्चा और राज्यों के परामर्श के बिना जल्दबाजी में बनाया गया था. कृषि से जुड़ी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और कीमतों के संदर्भ में इन केंद्रीय कानूनों का किसानों और उपभक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता नजर आने लगा है, क्योंकि ये अधिनियम किसानों और उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ हैं. ममता ने अपनी चिट्ठी में आगे कहा है कि यह उल्लेख किया जा सकता है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन के चलते अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है, जिसके बाद आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी कर मुनाफा बनाया जा रहा है. इस कारण आलू, प्याज आदि जैसी वस्तुओं की कीमतों में हुई वृद्धि से आम लोगों को तकलीफें हुईं. ममता ने अपनी चिट्ठी में आगे लिखा है कि इस संबंध में हमारी सबसे बुरी आशंका पहले से ही सही प्रतीत हो रही है क्योंकि हाल के हफ्तों में आवश्यक घरेलू सब्जियों जैसे आलू और प्याज की अत्यधिक कीमतों ने उन्हें पहले ही आम लोगों की पहुंच से दूर कर दिया है. ममता ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उन्हें नियमित करने का भी कोई संकेत नहीं है ना ही उनकी पर्याप्त आपूर्ति हो रही है. अंत में ममता बनर्जी ने कहा है कि आलू-प्याज जैसी आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती अप्रत्याशित कीमतों की वजह से बनी गंभीर स्थिति की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं और तत्काल हस्तक्षेप की उम्मीद अपेक्षा करती हूं, क्योंकि अब यह मामला राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, और हम महंगाई से जूझ रही जनता को मूकदर्शक बनकर देखते नहीं रह सकते.

राष्ट्रीय राजमार्गों का सड़क सुरक्षा होगा ऑडिट

मिली गड़बड़ी तो निर्माण कंपनियों को लागू करने होंगे सुझाव उपाय

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों का सड़क सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत स्वतंत्र सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम पूरी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का किलोमीटर वार ऑडिट करेंगे। इससे राजमार्गों के सड़क सुरक्षा त्रुटियों का पता लगाया जा सकेगा। इसके पश्चात ऑडिट रिपोर्ट में विशेषज्ञों के सुझाव-उपायों को निर्माण कंपनियों को लागू करना होगा। इस पहल का मकसद सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और निर्दोषों की जान बचना है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रायल ने नौ नवंबर को राज्यों के मुख्य सचिव, पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर, बीआरओ के डीजी, एनएचएआई के चेयरमैन, एनएचएआईडीसीएल के एमडी को पत्र लिखा है। इसमें उल्लेख है कि सभी चरणों के राष्ट्रीय राजमार्गों का सड़क सुरक्षा ऑडिट करने के लिए स्वतंत्र सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों को नियुक्ति किया जाए। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि तकनीकी रूप से राजमार्गों का चार चरणों में सड़क सुरक्षा ऑडिट कराना तय हुआ है। इसमें प्रथम चरण में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के प्रारंभिक डिजाइन का ऑडिट किया जाएगा। इसके पश्चात राजमार्ग का पूर्ण

डिजाइन तैयार होने पर और राजमार्ग के निर्माण के दौरान ऑडिट करना शामिल है। चौथे चरण में नए राजमार्ग पर यातायात शुरू करने से पहले अथवा मौजूदा राजमार्ग के चौड़ीकरण के पश्चात ऑडिट किया जाएगा। इसकी अवधि 12 माह से 36 माह तक हो सकती है यह राजमार्ग परियोजना पर निर्भर करेगा। इसके अतिरिक्त मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक का ऑडिट करना भी शामिल है। मंत्रायल के आदेश के बाद सभी केंद्रीय एजेंसियां व पीडब्लयूडी निर्माण कंपनियों से स्वंत्रत सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात करेंगी।

सड़क सुरक्षा ऑडिट क्या है-किसी भी नए अथवा विकसित राष्ट्रीय राजमार्ग पर आम लोगों के लिए यातायात शुरू करने से पहले उसका सड़क सुरक्षा ऑडिट कराना अनिवार्य होता है। नियमत- ऑडिट के बगैर राजमार्ग पर यातायात शुरू नहीं किया जा सकता है। रेलवे में भी नए ट्रैक पर रेल सुरक्षा आयुक्त के ऑडिट व मंजूरी के बगैर ट्रेन नहीं चलाई जा सकती हैं। विशेषज्ञ राजमार्ग पर सड़क सुरक्षा उपाय जैसे फुटओवर ब्रिज, अंडरपास, डिवाइडर, स्पीड ब्रेकर, मोड की तीव्रता, ढाल, पेव शोल्डर, इंटरचेंज, रेलवे क्रासिंग, बाजार के पास वाहन की रफ्तार के साइन बोर्ड, सड़क संकेतक व अन्य व्यवधान संबंधी बोर्ड आदि का अपनी ऑडिट रिपोर्ट में उल्लेख करते हैं। निर्माण कंपनियां पैसे बचाने के लिए सड़क सुरक्षा उपायों से समझौती कर लेती हैं।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संपादकीय

पटाखों पर पाबंदी

दीपावली की पहचान बन चुके पटाखों की विदाई का वक्त शायद अब आ गया है। कम से कम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस बार त्योहार पर न तो उनकी आवाज सुनाई देगी और न उनकी चकाचौंध दिखाई देगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने उन पर पाबंदी लगा दी है। यह पाबंदी 30 नवंबर तक जारी रहेगी। यानी इस बीच दीपावली, छठ और गुरुपरब जैसे कई पर्व बीत जाएंगे। यह पाबंदी सिर्फ दिल्ली और उसके आस-पास के क्षेत्रों के लिए ही नहीं है, बल्कि उन सभी क्षेत्रों के लिए है, जहां हवा की गुणवत्ता बहुत खराब है। जिन शहरों में हवा की गुणवत्ता मध्यम दर्जे की है, वहां पटाखे चलाने की छूट सिर्फ दो घंटे ही मिलेगी। अधिकरण ने इस अनुमति का समय भी तय कर दिया है और इस दौरान भी लोग कम प्रदूषण वाले ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल ही कर सकेंगे। राजधानी क्षेत्र में इस समय प्रदूषण का जो स्तर है, उसके बाद इस तरह की पाबंदी की जरूरत भी थी। यहां वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर को पार कर गया है। जाहिर है, किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जा सकती। वैसे देश के अन्य बड़े शहरों की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। दिल्ली समेत कई राज्यों की सरकारें पहले ही पटाखों और आतिशबाजी पर पाबंदी लगाने की घोषणा कर चुकी हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के फैसले ने पाबंदी के इस तर्क को और मजबूत कर दिया है।

दीपावली अब सिर्फ पांच दिन दूर है और इस लिहाज से यह दुरुस्त फैसला भी देर से आया हुआ फैसला ही लगेगा। इस समय तक पटाखे बाजारों में पहुंच चुके हैं और उनसे सज चुकी दुकानों की तस्वीरें भी अखबारों में छपने लगी हैं। ये दुकानें तो अब बंद हो जाएंगी, लेकिन मुमकिन है कि दुकानदार किसी न किसी रूप में इन्हें खपाने की कोशिश करें। देर से लगी पाबंदी अब प्रशासन के लिए अलग तरह की चुनौतियां पेश करेगी। यह समस्या हर साल इसी तरह से आती है और पाबंदी के बावजूद हर बार दीपावली की रात रह-रहकर पटाखों की आवाज सुनाई देती है। पाबंदियों को कड़ाई से लागू करना चाहिए। ऐसे फैसले अगर समय रहते हो जाएं, तो बहुत सारी चीजों से बचा जा सकता है।

इसके साथ ही ग्रीन पटाखों की चर्चा भी जरूरी है। पिछले काफी समय से ऐसे पटाखों की बहुत चर्चा रही है, जिनसे परंपरागत पटाखों के मुकाबले प्रदूषण कम होता है। प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे राज्यों की सरकारें ऐसे पटाखों के इस्तेमाल की अपील करती भी दिखाई देती हैं। हालांकि, बहुत से लोगों का अनुभव यही है कि चर्चा के बावजूद इस तरह के पटाखे बाजार में आसानी से नहीं मिलते। एक शिकायत यह भी है कि ऐसे पटाखे परंपरागत पटाखों के मुकाबले महंगे और कम आकर्षक होते हैं। जब तक एक साथ दोनों ही तरह के पटाखे बाजार में उपलब्ध रहेंगे, ग्रीन पटाखे बाजार नहीं पकड़ सकेंगे। पूरे पटाखा उद्योग पर एक साथ पाबंदी लगाना शायद संभव न हो सकेगा, लेकिन यह तो किया ही जा सकता है कि परंपरागत पटाखे बनाने पर सख्ती से पाबंदी लगाई जाए और सिर्फ ग्रीन पटाखों के उत्पादन की अनुमति हो। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में इस तरह की पाबंदियां लगाने में हम कामयाब रहे हैं और कुछ ऐसी गाड़ियां भी आ रही हैं, जो पहले से कम प्रदूषण करती हैं। अगर यह काम गाड़ियों के मामले में किया जा सकता है, तो पटाखों के मामले में क्यों नहीं हो सकता?

फिर से बेकाबू कोरोना

राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के साथ कोविड-19 का लगातार बढ़ रहा संक्रमण एक गंभीर चिंता का विषय है। चिंता का विषय यह भी है कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रदूषण और स्मॉग का महमारी पर क्या असर पड़ेगा। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों की वायु गुणवत्ता का स्तर काफी खराब स्थिति में पहुंच गया है। सर्दियों के मौसम की शुरुआत होते ही यह आशंका जताई जा रही थी कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण दोबारा बढ़ सकता है और यह आशंका सच साबित हो गई है। महामारी विशेषज्ञों की समिति ने अपने एक अध्ययन में यह अनुमान लगाया था कि नवम्बर महीने के अंत तक रोजाना 12 से 14 हजार कोरोना संक्रमण के नये मामले आ सकते हैं। बीते रविवार को कोरोना के 7,745 नये मामले सामने आए, जो अबतक का सर्वाधिक है। महामारी से 24 घंटे में 77 लोगों की मौत हो गई और एक दिन में कोरोना संक्रमण की दर 12.11 फीसद से बढ़कर 15.26 फीसद हो गई। इस तथ्य से सभी परिचित हैं कि कोरोना विषाणु नामक अदृश्य शत्रु अभी जीवित है और इसे मारने के लिए न तो कोई दवाई उपलब्ध है और न ही इसका टीका तैयार हुआ है। आर्थिक गतिविधियां और कारोबार शुरू करने के लिए जब लॉकड़ाउन हटाया गया तो लोगों ने मान लिया कि कोरोना खत्म हो गया और सार्वजनिक जीवन में लापरवाही बरतने लगे। हालांकि पर्व और त्योहारों के आने के पहले ही प्रधानमंत्री ने देशवासियों को सतर्क किया था और इस महामारी के विरुद्ध संघर्ष तेज करने के लिए जनआंदोलन की शुरुआत भी की। उन्होंने 'जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं' का मंत्र भी दिया, लेकिन लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। यही वजह है कि दिल्ली कोरोना महामारी की तीसरी लहर की चपेट में आ गया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि कोविड-19 के लिए गठित नेशनल टास्क फोर्स के सदस्य और एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि आम लोगों को टीका के लिए 2022 तक इंतजार करना पड़ेगा। उनकी इस सूचना में चेतावनी भी झलक रही है। उनकी बात का यह आशय निकाला जाना चाहिए कि 2022 तक लोगों को महामारी से बचने के लिए मास्क पहनना होगा, हाथ साफ रखने होंगे और सामाजिक दूरी का पालन करना होगा।

टू दि प्वाइंट/ आलोक पुराणिक

जो आएगा, वह जाएगा

मतलब मोटे तौर पर लगभग, करीब-करीब यह माना जा सकता है कि ट्रंप जा रहे हैं और बाइडेन आ रहे हैं। मतलब मानने में क्या बुराई है। हालांकि ट्रंप इस बात को नहीं मान रहे हैं वह कानूनी लड़ाई लड़ेंगे ऐसा कहा जा रहा है। बाइडेन आएंगे, ऐसा भी माना ही जा रहा है। विकट कन्फ्यूजन है। किसे मानें किसे ना मानें। ट्रंप नाराज हो सकते हैं इस बात पर कि उन्हें अब क्यों नहीं राष्ट्रपति माना जा रहा है। मेरा ऐसा अंदाज है कि जिन राष्ट्राध्यक्षों ने बाइडेन को बधाई दी है, उन्होंने चुपके से ट्रंप को भी फोन किया होगा-जी हम तो दिल से आपको ही मानते हैं राष्ट्रपति, पर शर्मा-शर्मी में बाइडेन को भी बधाई देनी पड़ती है, क्योंकि वह भी अब खुद को राष्ट्रपति मानने लगे हैं।

ट्रंप खुद को भूतपूर्व मानने को तैयार नहीं हैं। अभूतपूर्व स्थिति है।

जो आया है, वह जाएगा, पर जो जाएगा वह आ भी सकता है जी। यह भी सोच लेना चाहिए।

चार साल बाद फिर ट्रंप का दांव लग सकता है। पर वह पहले जाएं, तो। वापस आने के लिए जाना जरूरी होता है। ट्रंप जिस हिसाब के नेता हैं, वह यह भी कह सकते हैं बाइडेन से कि भाई इतना बड़ा व्हाइट हाउस है, आधा तू रख ले, आधे में मैं रह लूंगा। मुझे तो चार साल बाद आना ही है। तमाम आयोजनों में ट्रंप भी आ सकते हैं, भविष्य के राष्ट्रपति के बतौर। बिडेन कह रहे हैं कि जीत गया और ट्रंप कह रहे हैं कि अभी हारा नहीं। चीन खुश है, कि चलो ट्रंप गए, पर पर फिर चीनी हुक्मरान रुककर सोचते हैं कि क्या वाकई में ट्रंप चले गए। व्हाइट हाउस के कतमयों की बड़ी आफत आने वाली है, जिसे राष्ट्रपति नहीं मानो, वही धमका लेगा। एक ही व्हाइट हाउस में दो राष्ट्रपति कैसे रह सकते हैं। रह सकते हैं॥। व्हाइट हाउस में कौन रहेगा-यह सवाल अधिकांश भारतीयों के लिए व्यर्थ है, उनके लिए सवाल यह है कि कोरोना के हल्ले में नौकरी रहेगी या नहीं। पर यह सवाल फिलहाल कई भारतीय भूल चुके हैं, इसे भी ट्रंप अपनी सफलता के तौर पर चिह्नित कर सकते हैं।

बाइडन की विजय में शामिल भारत

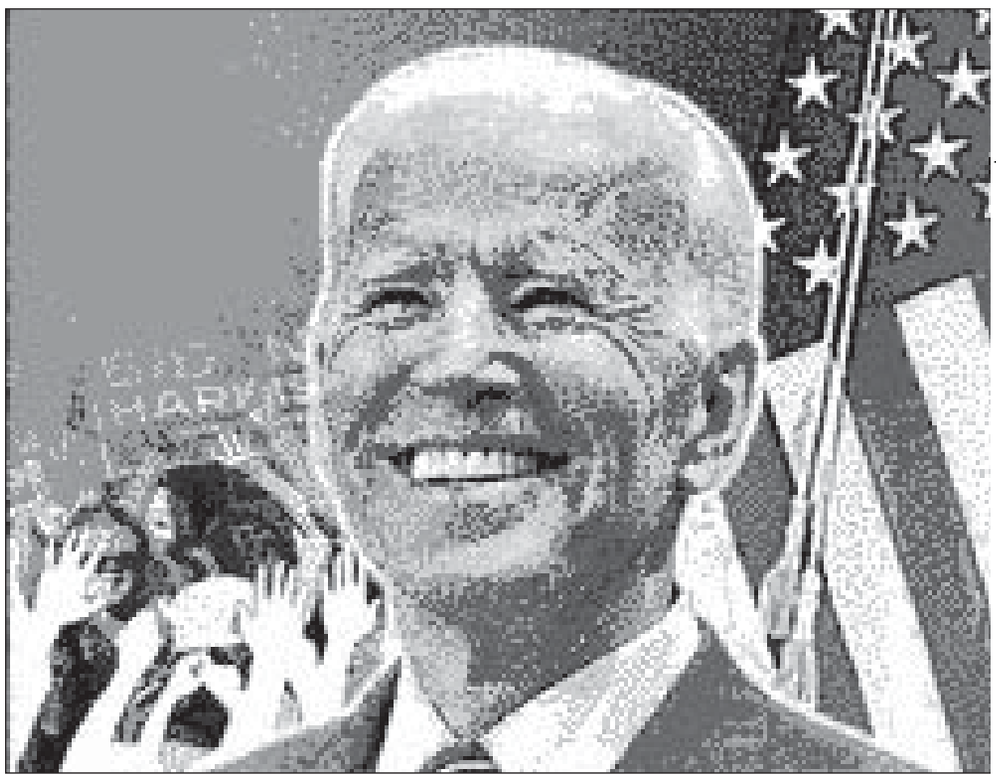

फ्रैंक एफ इस्लाम

अमेरिका के उप-राष्ट्रपति रह चुके जो बाइडन ने बेहद कड़े मुकाबले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (अब निवर्तमान) को मात दे दी, जबकि मतदान पिछली एक सदी के सबसे बड़े स्वास्थ्य संकट के बीच हो रहे थे। इस चुनाव पर तीन वजहों से भारत की गहरी नजर थी। पहली, डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर भारतीय मूल की एक उम्मीदवार का उप-राष्ट्रपति पद के लिए मैदान में होना; दूसरी, अमेरिका की राजनीति में भारतवंशी अमेरिकियों को मिलता महत्व; और तीसरी, विदेश नीति की दशा-दिशा, जो हर नई सरकार अपने तरीके से तय करती है।

प्रतीकात्मक रूप से देखें, तो भारतीय मूल के अमेरिकियों के लिए जो बाइडन की जीत एक नए युग की शुरुआत है, क्योंकि अब कमला हैरिस की ताजपोशी उप-राष्ट्रपति पद पर होने वाली है। कैलिफोर्निया की इस सीनेटर का यहां तक पहुंचना न सिर्फ भारतवंशी अमेरिकियों के लिए, बल्कि अफ्रीकी अमेरिकियों, अन्य अल्पसंख्यक समूहों और महिलाओं के लिए भी एक ऐतिहासिक मौका है।

इसके अलावा भी कई अन्य सकारात्मक बातें भारतीय मूल के अमेरिकी समुदाय के पक्ष में हैं। मसलन, दोनों पार्टियों (रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक) ने अपने चुनाव अभियान में इस समुदाय का समर्थन पाने के लिए खासा जतन किए, विशेषकर पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, उत्तरी कैरोलिना जैसे स्विंग राज्यों में, जहां मतदाताओं का रुझान स्पष्ट नहीं था।

इसके अलावा अमेरिकी निचले सदन, यानी 'हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव' के लिए चार भारतवंशी अमेरिकियों का फिर से चयन भी इस समुदाय के लिए जश्न मनाने का मौका है। अमी बेरा, रो खन्ना, प्रमिला जयपाल और राजा कृष्णमूर्ति, सभी ने डेमोक्रेटिक के टिकट पर आसान जीत दर्ज की है। राज्यों व स्थानीय निकायों के चुनावों में भी एक दर्जन से अधिक भारतीय अमेरिकियों ने सफलता हासिल की है, जिनमें से पांच महिलाएं हैं। इससे सत्ता-तंत्र के विभिन्न स्तरों पर भारतवंशी अमेरिकी समुदाय का प्रतिनिधित्व बढ़ा है।

वैसे, कुछ भारतीय अमेरिकियों को मायूसी भी हाथ लगी है। जैसे, लोकप्रिय होने के बावजूद सारा गिडिअन अपनी प्रतिद्वंद्वी सीनेटर सुसान कोलिन्स को हराने में सफल नहीं हो सकीं। पूर्व राजनयिक प्रेस्टन कुलकर्णी भी टेक्सास के 22वें जिले में कांग्रेस की जंग नहीं जीत सके। एक अन्य भारतीय अमेरिकी एरिजोना के छठे जिले में बहुत मामूली अंतर से पराजित हुईं। ये तीनों डेमोक्रेट हैं। इनको भले ही हार का मुंह देखना पड़ा है, लेकिन इससे इस समुदाय की उपलब्धि कम नहीं हो जाती। चुनावी चक्र में विभिन्न स्तरों पर पहले से कहीं अधिक भारतवंशी अमेरिकियों की उम्मीदवारी इसकी तस्दीक करती है।

बहरहाल, भारत-अमेरिका संबंधों के हिमायतियों को फिर से आश्वस्त हो जाना चाहिए कि अब ह्वाइट हाउस के ओवल ऑफिस (राष्ट्रपति-कार्यालय) में एक ऐसा शख्स आने वाला है, जो पदभार ग्रहण करते समय किसी भी अन्य अमेरिकी राष्ट्रपति से कहीं अधिक भारत से परिचित है। बतौर सीनेटर और उप-राष्ट्रपति जो बाइडन भारत के अच्छे दोस्त और अहम हितैषी रहे हैं। वैसे, दिल्ली में कुछ ऐसे राजनीतिक पंडित भी हैं, जो मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए कहीं बेहतर साबित होते। सुबूत के तौर पर वे कश्मीर और नागरिकता संशोधन विधेयक के मसले पर उनकी चुप्पी की ओर इशारा करते हैं। निश्चय ही, भारत में कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप के रिश्ते को नई दिल्ली के लिए फायदेमंद मानते रहे हैं। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान ह्यूस्टन में 'हाउदी मोदी' कार्यक्रम में दोनों शासनाध्यक्ष एक साथ मंच पर आए भी थे। उस आयोजन में लगभग 50 हजार भारतवंशी अमेरिकियों ने शिरकत की थी।

इस साल फरवरी में भी अपने दो-दिवसीय भारत-दौरे के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अहमदाबाद में एक बड़ी रैली को संबोधित किया था। दोनों मुलाकातों को भारत-अमेरिका के आपसी रिश्तों के लिए सुखद माना जा सकता है, लेकिन सच यही है कि भारत के प्रति ट्रंप का रवैया शुरू से ही लेन-देन का रहा। दोनों सियासी आयोजनों का फायदा अमेरिकी राष्ट्रपति को तो हुआ, लेकिन ये आयोजन भारत के लिए किसी सार्थक लाभ में नहीं बदल सके। देखा जाए, तो ट्रंप के कार्यकाल में द्विपक्षीय कारोबारी और आर्थिक रिश्ते खराब ही हुए हैं। एक व्यापारिक समझौता तक नहीं हो सका, जिसकी उम्मीद की जा रही थी।

इसी तरह, ए-1बी वीजा के मसले पर डोनाल्ड ट्रंप की आप्रवासी विरोधी नीतियों का भी भारत पर और अमेरिका में काम कर रहे भारतीय मूल के लाखों कामगारों पर प्रतिकूल असर पड़ा है। हालांकि, जो बाइडन ने वायदा किया है कि वह ट्रंप की आव्रजन और आर्थिक नीतियों को उलट देंगे। इससे भारत और अमेरिका का द्विपक्षीय रिश्ता निश्चय ही मजबूत होगा और व्यापक स्तर पर आपसी संबंधों में सुधार आएगा। यह सही है कि कई राज्यों में वोटों की गिनती काफी धीमी रही, जिस कारण नतीजे आने में वक्त लगे। इसको लेकर भारत में काफी-कुछ कहा भी गया। सोशल मीडिया के कुछ वीर तो भारतीय चुनाव प्रणाली की श्रेष्ठता के गुण गाने लगे, जहां परिणामों की घोषणा आमतौर पर 12 घंटे में हो जाती है। मगर इस बाबत यह जान लेना चाहिए कि अमेरिका में चुनाव की प्रक्रिया कोई एक केंद्रीय एजेंसी पूरी नहीं करती, जैसा कि भारत में निर्वाचन आयोग पूरे देश में चुनाव कराता है। यहां तो बेहद स्थानीय स्तर पर इसे पूरा किया जाता है। राज्यों के साथ यहां 3,100 से अधिक काउंटी में बैलेट पेपर जारी करने से लेकर मतगणना व नतीजों को प्रमाणित करने जैसे दुरूह काम किए जाते हैं। फिर, इस साल कोविड-19 महामारी के कारण कई सारे मतदाताओं ने 'मेल-इन बैलेट' का इस्तेमाल किया। वेबसाइट से आए वोटों को गिनने की तुलना में इन मतपत्रों की सूची बनाना और इनकी सटीकता सुनिश्चित करना काफी मुश्किल है। हालांकि, ऐसा करना चुनावों की निष्पक्षता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लोकतंत्र को बेदाग बनाता है। यही वजह है कि वोटों की गिनती में लगने वाला वक्त और धीमी मतगणना-प्रक्रिया को अमेरिकी लोकतंत्र की कमजोरी न समझा जाए। वे इसकी ताकत को दर्शाते हैं।

जाहिर है, इस ऐतिहासिक चुनावी वर्ष में जो बाइडन भी जीते हैं और अमेरिकी लोकतंत्र भी। यह न सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए, बल्कि भारत और शेष दुनिया के लिए भी सुखद है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

> उन्होंने वायदा किया है कि वह ट्रंप की आव्रजन और आर्थिक नीतियों को उलट देंगे। इससे भारत से द्विपक्षीय रिश्ता निश्चय ही मजबूत होगा।

कृषि कानून

कांग्रेस ने भी किसानों को अधर में छोड़ा

राजेन्द्र चौधरी

हाल में पारित कृषि कानूनों के माध्यम से मोदी सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में लाई गई '1991 सरीखी क्रांति' का देश भर में विरोध हो रहा है। तीन कांग्रेस शासित राज्यों ने विधानसभा में कानून पास कर केन्द्रीय कानून को भोथरा करने और किसानों के हितों की रक्षा करने का दावा किया है। सबसे पहले पंजाब ने, फिर छत्तीसगढ़ और राजस्थान ने इस आशय के कानून बनाए हैं।

मान्यता यही रही है कि तीनों कांग्रेस शासित राज्यों में पारित कानून एक जैसे होंगे। पर वास्तव में ऐसा नहीं है। तीनों कांग्रेस शासित राज्यों में पारित कृषि सम्बन्धी कानूनों में न केवल काफी अंतर है, अपितु वे मोदी सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में लाई गई '1991 सरीखी क्रांति' यानी बाज़ार आधारित अर्थव्यवस्था के मूल तत्वों को बरकरार रखते हैं।

पंजाब ने केवल गेहूं एवं धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम पर खरीदी को गैरकानूनी घोषित किया है, तो छत्तीसगढ़ के कानून में न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी कोई प्रावधान नहीं है, और राजस्थान ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को केवल करार खेती कानून के तहत अनिवार्य किया है—बाकी जगह बिक्री के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को अनिवार्य नहीं किया। इतना फर्क अवश्य है कि जहां पंजाब ने केवल गेहूं और धान के लिए इसे अनिवार्य किया है, वहीं राजस्थान ने इसे सभी फसलों के लिए अनिवार्य किया है (पर केवल करार खेती कानून के तहत)। लेकिन इन तीनों कांग्रेस सरकारों ने किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने का कोई ठोस प्रावधान नहीं किया है।

एक काम जो सभी कांग्रेस शासित सरकारों ने किया है, वह यह है कि मंडी कर सभी तरह की कृषि उपज की खरीद पर लगेगा, फिर चाहे वह सरकारी मंडी में हो, निजी मंडी में, मंडी से बाहर हो या अनुबंध खेती के तहत। इस बदलाव से राज्य सरकार के राजस्व पर पड़ने वाले केन्द्रीय कानून के दुष्प्रभाव निरस्त हो जायेंगे। केन्द्रीय कानून के चलते मंडी खरीद, मंडी से बाहर की खरीद के मुकाबले महंगी हो गई थी, अब यह प्रभाव भी निरस्त हो जाएगा पर इसका किसानों को मिलने वाले भाव पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। राजस्थान ने करार खेती के तहत बिक्री और नियंत्रित मंडी से बाहर हुए सौदों में विवाद होने पर मंडी कानून के तहत ही कार्रवाई का प्रावधान किया है। विवाद की स्थिति में लागू होने वाले कानूनी प्रावधानों में कुछ बदलाव छत्तीसगढ़ और पंजाब में भी किये गए हैं।

इन कानूनी बदलावों के माध्यम से राज्य सरकारों ने कृषि क्षेत्र पर राज्य सरकार के नियंत्रण का कानूनी दावा ठोका है और यह स्वागत योग्य है। परन्तु दो बड़े मुद्दों पर ये राज्य सरकारें मोदी सरकार की राह पर ही चली हैं। इनमें से एक, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों को खरीद का कोई आश्वासन नहीं। दूसरा है करार खेती के नाम पर कम्पनियों द्वारा खेती की जो राह मोदी सरकार ने खोली है, उस पर रोक लगाने के बजाय राजस्थान सरकार ने इसे और भी स्पष्ट कर दिया है। राजस्थान द्वारा पारित करार खेती संबंधी कानून की धारा 6 के तहत इस आशय का प्रावधान है कि प्रायोजक, यानी किसान से करार करने वाला, अपने द्वारा लगाए गए श्रमिकों को करार खत्म होते ही खेत से हटा लेगा। इससे स्पष्ट है कि करार खेती कानून के तहत करार केवल पैदवार की बिक्री का नहीं होगा अपितु सब तरह के कृषि कार्य यानी खेती का भी होगा। यद्यपि केन्द्रीय कानून की धारा 8 ए के तहत इसका निषेध किया गया था परन्तु इसी कानून की धारा 2 डी, 2 जी द्वद्ध एवं 8 बी के तहत कम्पनियों द्वारा खेती के लिए अप्रत्यक्ष प्रावधान था। लेकिन केन्द्र द्वारा पारित कानून के मसविदे के पृष्ठ 11 पर उद्देश्यों एवं कारणों पर प्रकाश डालने वाले हिस्से से केंद्र की मंशा स्पष्ट हो जाती है।

इस हिस्से की शुरुआत ही भारत की कृषि में 'छोटी-छोटी' जोतों से पैदा होने वाली समस्या गिनवाने से होती है। स्पष्ट है कि छोटी-छोटी जोतें तो तभी ख़त्म हो सकती हैं जब खेती कम्पनियों द्वारा होने लग जाए। केन्द्रीय कानून में जो बात कुछ हद तक दबी छुपी थी, वह राजस्थान के कानून में स्पष्ट हो गई है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि दोनों, भाजपा और कांग्रेस, देश की अर्थव्यवस्था में 1991 में आए बदलावों को, यानी देश की अर्थव्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा कम्पनियों के हवाले करने के रास्ते पर चलते हुए, अब कृषि क्षेत्र को भी उसमें शामिल करना चाहती हैं।

उत्तराखंड

अब तस्वीर बदलनी चाहिए

आशीष रावत

नब्बे के दशक में उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की मांग ने जब गति पकड़ी तो इसका मूल कारण यह रहा कि विकास के मामले में उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में पर्वतीय जिलों की घोर उपेक्षा होती थी।

उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद बनी किसी भी सरकार ने इस गम्भीर समस्या के समाधान के लिए ईमानदार पहल नहीं की। अपितु मैदानी इलाकों को तेजी से विकसित करने की सरकारी नीति से असंतुलित विकास की स्थिति पैदा हो गई, जिससे पहाड़ से मैदान की तरफ होने वाले पलायन को बढ़ावा ही मिला। उत्तराखंड का इतिहास इसके गौरवपूर्ण अतीत का गीत गाता है। इसकी उत्पत्ति और विकास का लम्बा इतिहास रहा है।

भारत के मानचित्र पर जिस उत्तराखंड को 9 नवम्बर, 2000 को उकेरा गया था उसके पीछे कई प्रश्न थे। उम्मीद जताई गई थी कि आंदोलन की उपज उत्तराखंड की पीड़ा को स्थानीय सियासत समझ पाएगी और पहाड़ी राज्य के रिसते घावों पर नीतियों का मरहम लगेगा। मगर अफसोस पहली अंतरिम सरकार विकास का कोई खाका खींच ही नहीं पाई और पहली निर्वाचित सरकार उत्तर प्रदेश के अंदाज में ही राज्य को तथाकथित विकास के कच्चे-पक्के रास्ते पर घसीटते रही। दूसरी निर्वाचित सरकार से पहाड़ी राज्य की जनता ने उम्मीद पाली कि जल-जंगल-आबोहवा, पहाड़ के सुलगते प्रश्नों का जवाब मिलेगा। नई सरकार राज्य के सरोकारों के साथ कोई विकास का रोडमैप बनाएगी, लेकिन अफसोस वो सरकार पिछली सरकार के घोटालों पर हल्ला और अपनी गुटबाजी को सुलझाती रह गई।

फिर चुनाव में जनता ने मौसेरे भाई पर भरोसा किया, लेकिन गुटबाजी और घोटालों के जिन्न ने पीछा नहीं छोड़ा। सियासत जनता का भरोसा खो गई और पहाड़ की युवा शक्ति पगडंडियों से उतरते हुए दूर महानगरों में खो गए। 18 वर्ष के जवान की 16 वर्ष की जवां उम्र महानगर खा गए अब अधेड़ उम्र में दहलीज पर खड़ा स्वप्नदृष्टा युवा का पहाड़ से मोहभंग हो गया नतीजतन पहाड़ रीते हो गए। ये राज्य की 20 वर्ष की सियासत पर तमाचा नहीं तो क्या है? हर बार चुनावी घड़ी आती है और वीरान पहाड़ों के उदास कस्बों में बेशर्म सियासत फिर से, 'वोट दो' का राग अलापती है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में जीविकोपार्जन की जटिलता, संघर्ष और रोजगार के समुचित अवसर ना होने ने पलायन को बढ़ावा दिया है। यहां जीवन सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं, बल्कि रात को वो घना तिमिर है, जब प्रकृति की हरियाली भी सघन अंधेरे से ढक जाती है। ग्रामीण आबादी रोजगार की तलाश और सुविधा सम्पन्न जीवन के लिए शहरों में जा रही है। खेत-खलिहान बंजर होते जा रहे हैं। गांवों के गांव खाली हो गए हैं। विकास के सही रोडमैप के अभाव, नीति-नियंताओं और हुक्मरानों की निष्क्रियता, दूरदृष्टि और सही विजन की कमी ने जिस परिकल्पना से इस पहाड़ी राज्य का गठन हुआ था, उस पर बट्टा लगा दिया है। युवा पीढ़ी पढ़ाई और रोजगार के लिए दूसरे शहरों में जाती है और वहीं की होकर रह जाती है। राज्य सरकार के पास ऐसी कोई नीति नहीं है, जिसके तहत यहां का युवा पहाड़ के विकास के लिए काम करे। राज्य निर्माण के बाद भाजपा और कांग्रेस, दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियों की सरकारें आई और गई। पहाड़ी राज्य के विकास को लेकर विज़न का अभाव बना ही रहा।

ग्रामीण आबादी शहरी क्षेत्र की तरफ सिमट रही है। पहाड़ वीरान हो रहे हैं। सुविधाओं के अभाव, प्राकृतिक आपदाओं की मार और रोजगार की कमी की वजह से अपना घरबार छोड़ उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के बाशिंदे बड़े शहरों की ओर रु ख कर रहे हैं। ऐसे गांवों की संख्या हजार को पार कर गई है, जहां अब कोई रह ही नहीं रहा। उत्तराखंड में पलायन खतरनाक हद तक पहुंचता जा रहा है। गांव के गांव खाली हो रहे हैं। पलायन हालांकि इस राज्य की पुरानी समस्या रही है, लेकिन वर्ष 2013 में आई आपदा ने इसकी रफ्तार को और बढ़ा दिया है। यह स्वीकार करना होगा कि अलग उत्तराखंड राज्य बनने के बाद पलायन की रफ्तार और संख्या में थोड़ा बहुत कमी जरूर दर्ज हुई, लेकिन इस कमी को उच्च शिक्षित जमात ने पूरा कर दिया है। पृथक उत्तराखंड के लिए भले ही उत्तराखंड की एक पीढ़ी ने दिन-रात एक कर दिया हो, भले ही उस पीढ़ी के सैकड़ों नौजवानों ने जान गंवा दी हो, लेकिन अलग राज्य बनने के बाद भी सपनों का उत्तराखंड सपनों में ही है। विकास हुआ है तो सिर्फ नेताओं का। पलायन का असर खेती पर भी पड़ा है। ऐसे में विचारणीय प्रश्न है कि पिछली सरकारों ने पलायन रोकने के लिए क्या किया और मौजूदा सरकार क्या कर रही है?

हाउसिंग फाइनेंस के क्षेत्र में उतरी गोदरेज समूह, शुरू की नई कंपनी

मुंबई। देश की अग्रणी कंपनी गोदरेज समूह ने हाउसिंग काइनेंस कंपनी में उतरने का ऐलान किया है। इस नई कंपनी का नाम गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस रखा गया है। गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस के चेयरमैन पिरोजशा गोदरेज ने कहा कि उनकी कंपनी देश में उचित, शीघ्रतापूर्ण एवं लचीले होम लोन प्रदान करवाएगी। शुरूआती दौर में योजना मुंबई, एनसीआर, पुणे और बेंगलुरू के ग्राहकों को उपलब्ध होगी। रियल्टी सेक्टर के लिहाज से यह चारों शहर देश में प्रमुख माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस, गोदरेज प्रोपर्टीज जैसे डेवलपर्स के साथ मिलकर उनके मौजूदा और नये ग्राहकों को बेहतरीन वित्त पोषण का अनुभव प्रदान करेगा। उनके मुताबिक गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस द्वारा ऑफर किए जाने वाले उत्पाद तीन पिलरों पर टिके हैं। ये तीन पिलर हैं फ्लेक्जिबिलिटी (ग्राहकों को उनके अपने अंशदान के भुगतान और ईएमआई शेड्युल को इच्छानुरूप करने में सक्षम बनाना), अफोर्डेबिलिटी (6.69त्न की न्यूनतम शुरुआती ब्याज दर के साथ प्रतिस्पर्द्धी कीमत की पेशकश) और पर्सनलाइजेशन (माइक्रोसेगमेंट ग्राहकों के लिए आंकड़ों के आधार पर निर्णय और विशेष ऋण पेशकश)। गोदरेज हाउसिंग फाइनेस का कहना है कि मॉरगेज बिजनेस जोर देते हुए होम लोन के साथ वह कारोबार की शुरुआत करना चाहता है। इसके बाद प्रोपर्टी पर लोन की सुविधा देना शुरू किया जाएगा। निकट भविष्य में, जीएचएफ, समूह के उपभोक्ता एवं कृषि व्यवसाय तंत्रों का उपयोग करके अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाते हुए बिजनेस और पर्सनल लोन्स को उपलब्ध करवाकर इन खंड़ों को मजूबत बनाएगा। इस नए बिजनेस लान्चिंग के मौके पर पिरोजशा गोदरेज ने कहा, हमें आज अपने वित्तीय सेवा व्यवसाय का शुभारंश करने की खुशी है। हमें उम्मीद है कि यह व्यवसाय गोदरेज समूह के विकास का एक अन्य महत्वपूर्ण स्तंभ बनेगा और हमने उस दिशा में अपना पहला कदम बढ़ाया है। रियल इस्टेट क्षेत्र के बढ़ते औपचारिकीकरण और रेजिडेंशियल रियल इस्टेट एवं हाउसिंग फाइनेंस बाजारों के विस्थापन ने वर्तमान समय में इसे विशेष रूप से आकर्षक अवसर बना दिया है।

अमेरिका की ओर से भारत का GSP दर्जा बहाल कर भेजा जा सकता है मजबूत संकेतः अघी

वाशिंगटन। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और वाशिंगटन द्वारा भारत के मामले में व्यापार से जुड़ी सामान्यीकृत तरजीही प्रणाली (जीएसपी) को बहाल कर देने से ही तुरंत एक छोटा व्यापार समझौता हो सकता है और इससे नयी दिल्ली को एक मजबूत संकेत भी भेजा जा सकता है। एक प्रमुख भारत केन्द्रित अमेरिकी व्यावसायिक पैरवी समूह ने यह कहा है। अमेरिका- भारत रणनीतिक एवं भागीदारी मंच (यूएसआईएसपीएफ) के अध्यक्ष मुकेश अघी ने पीटीआई- भाषा के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि भारत और अमेरिका जल्दी से इस तरह का एक छोटा सा व्यापार समझौता करके आगे बढ़ सकते हैं और आगे बड़े मुद्दों पर ध्यान लगा सकते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सितंबर में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच सीमित व्यापार समझौता करने के मामले में जितने भी मुद्दे आड़े आ रहे थे उनका समाधान कर लिया गया है इसके बाद अमेरिका की राजनीतिक स्थिति यदि इसकी अनुमति देती है तो किसी भी समय यह समझौता हो सकता है। भारत की ओर से अमेरिका के समक्ष जो मांगे रखी गई थी उनमें इस्पात और एल्यूमीनियम उत्पादों पर लगाये जा रहे ऊंचे शुल्क से छूट देने, जीएसपी के तहत भारत को कुछ निर्यात सामानों पर दिये जाने वाले लाभ को बहाल करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा कृषि, आटोमोबाइल, वाहन कलपुर्जे और इंजीनियरिंग उत्पादों को अमेरिका में बेहतर बाजार पहुंच उपलब्ध कराने को कहा गया। दूसरी तरफ अमेरिका की ओर से भारत के बाजारों में उसके कृषि और विनिर्मित उत्पादों, डेयरी सामानों और चिकित्सा उपकरणों के लिये अधिक बाजार पहुंच उपलब्ध कराने और साथ ही कुछ सूचना और दूरसंचार प्रौद्योगकी के उत्पादों पर आयात शुल्क कम करने की मांग की गई।

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, बैंक सभी खातों को अगले साल मार्च तक आधार से जोडें

मुंबई।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बैंकों से 31 मार्च, 2021 तक सभी खातों को संबंधित ग्राहकों की आधार संख्या से जोड़ने का काम सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेश की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अभी इसे आगे बढ़ाना बाकी है। कई ऐसे खाते हैं, जो अबतक आधार से नहीं जुड़े हैं। भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की 73वीं सालाना आम बैठक के संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा, 'प्रत्येक खाता 31 मार्च, 2021 तक आधार से जुड़ना चाहिए और जहां भी जरूरी तथा लागू हो, पैन से उसे जोड़ा जाना चाहिए।' उन्होंने यह भी कहा कि बैंकों को डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित और अन्य रूप से किये जाने को वाले भुगतान को हतोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने यूपीआई आधारित भुगतान को अपनाने पर भी जोर दिया। वित्त मंत्री ने कहा, 'यूपीआई हमारे सभी बैंकों में आम बोलचाल के शब्द होने चाहिए।' उन्होंने रूपे कार्ड को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया। सीतरमण ने कहा, ''जिसे भी कार्ड की जरूरत है, आप उहें केवल रूपे कार्ड ही जारी करें।''

उन्होंने कहा कि देश बड़े आकार के बैंकों पर जोर दे रहा है।

एनटीपीसी की औरैया परियोजना वाणिज्यिक रूप से चालू

नयी दिल्ली.

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनटीपीसी ने मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में औरैया परियोजना के तहत 8 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा क्षमता वाणिज्यिक रूप से परिचालन में आ गयी है। कंपनी के अनुसार परियोजना के अंतर्गत शेष 12 मेगावाट की क्षमता पर काम जारी है और इसके मार्च 2021 तक परिचालन में आने की उम्मीद है। बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने बीएसई को दी सूचना में कहा, ''उत्तर प्रदेश के औरैया में 20 मेगावाट क्षमता की ओरैया सौर पीवी परियोजना के तहत 8 मेगावाट क्षमता सफलतापूर्वक चालू हो गयी है।'' कंपनी की वेबसाइट के अनुसार उसकी कुल बिजली उत्पादन क्षमता 62,918 मेगावाट (संयुक्त उद्यम और अनुषंगी इकाइयों को मिलाकर) है। कुल क्षमता में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 883 मेगावाट है।

निर्यात में दिखे सुधार के संकेत, नवंबर के पहले सप्ताह में 22.47 प्रतिशत की वृद्धिः अधिकारी

नई दिल्ली। देश के निर्यात कारोबार में सुधार आने के संकेत दिखने लगे हैं। नवंबर के पहले सप्ताह में 6.75 अरब डालर का निर्यात किया गया जो कि सालाना आधार पर 22.47 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। इसमें औषधि, रत्न एवं आभूषण और इजीनियरिंग क्षेत्र का मजबूत योगदान रहा। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह कहा। एक साल पहले नवंबर के पहले सप्ताह में 5.51 अरब डालर का निर्यात किया गया था। इस लिहाज से इस साल नवंबर में इसमें 1.25 अरब डालर की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रतिशत में यह आंकड़ा 22.47 प्रतिशत रहा है। अधिकारी ने बताया कि 1 से 7 नवंबर 2020 के दौरान आयात 13.64 प्रतिशत बढ़कर 9.30 अरब डालर रहा जो कि एक साल पहले इसी अवधि में 8.19 अरब डालर रहा था। आयात में पेट्रोलियम को छोड़कर अन्य सामानों का आयात 23.37 प्रतिशत बढ़ा है। व्यापार घाटे की यदि बात की जाये तो यह 2.55 अरब डालर रहा है। औषधि, रत्न एवं आभूषणों का निर्यात आलोच्य अवधि में क्रमशः 32 प्रतिशत बढ़कर 13.91 करोड़ डालर, 88.8 प्रतिशत बढ़कर 336.07 करोड़ डालर पर रहा। इसी प्रकार इंजीनियरिंग सामानों का निर्यात 16.7 प्रतिशत बढ़कर 21.51 करोड़ डालर पर पहुंच गया।

दान के मामले में अजीम प्रेमजी ने मुकेश अंबानी को छोड़ा पीछे, रोजाना दान किए 22 करोड़ रुपए

बिजनेस डेस्कः

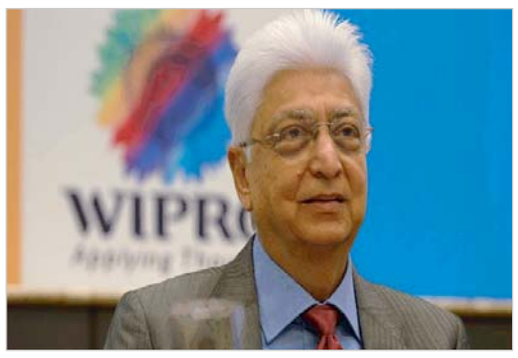

हुरून इंडिया (Hurun India) और श्वस्त्रद्दद्य-त्रद्ब1द्ग एडलगिव ने आज EdelGive Hurun India Philanthropy List 2020 (परोपकारी लोगों की लिस्ट) का सातवां एडिशन जारी किया है। इस लिस्ट में विप्रो के फाउंडर और चेयरमैन अजीम प्रेमजी ने टॉप किया है। उन्होंने कुल 7,904 करोड़ रुपए दान किए हैं यानी औसतन उन्होंने हर रोज 22 करोड़ रुपए दान दिए हैं।

मुकेश अंबानी तीसरे नंबर पर

वहीं एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ के फाउंडर और चेयरमैन शिव नाडर दूसरे नंबर पर हैं। हुरून इंडिया की इस लिस्ट में भारत के सबसे अमीर शख्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को तीसरा स्थान मिला है। इस लिस्ट में आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला को चौथा स्थान मिला है। वहीं 5वें नंबर पर हैं वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल।

कुल दान में हुआ 175 फीसदी का इजाफा

इस साल लिस्ट में शामिल लोगों के कुल दान में 175 फीसदी का इजाफा हुआ है और ये 12,050 करोड़ रुपए हो गई है। पिछले साल 10 करोड़ से अधिक की रकम दान करने वालों की संख्या 37 थी, जो इस साल 78 हो गई है। इस लिस्ट में सबसे अधिक 36 लोग मुंबई से हैं, जबकि दिल्ली दूसरे और बेंगलुरु तीसरे नंबर पर है। इस लिस्ट में बिन्नी बंसल अकेले परोपकारी हैं, जिनकी उम्र 40 साल से कम (37 साल) है।

पहली बार शामिल हुए 28 परोपकारी

इस लिस्ट में 28 परोपकारी लोग पहली बार शामिल हुए हैं। इन नए लोगों में इंफोसिस के एसडी शिबुलाल भी हैं, जिन्होंने 32 करोड़ रुपए दान में दिए हैं। उनके बाद एटीई चंद्र फाउंडेशन के अमित और अर्चना चंद्र का नंबर आता है, जिन्होंने 27 करोड़ रुपए दान दिए हैं। श्याम स्टील्स के श्री राम बेरिवाला और श्याम सुंदर बेरीवाला ने 19 करोड़ रुपए का दान दिया है। परोपकार और जन हितैषी कामों के लिए पैसे देने वालों की लिस्ट इस लिस्ट में कुल 112 लोगों को शामिल किया गया है और ये संख्या 2019 की लिस्ट से 12 फीसदी अधिक है।

उद्योग परिसंघ नवाचारों और अनुसंधानों की पहचान कर उन्हें आगे लाएं: मिश्र

जयपुर. राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने उद्योगों से अनुसंधान और डिजाइन के नवाचारों को प्रोत्साहित करने वाली संस्थागत प्रणाली विकसित करने का आह्वान किया है। उन्होंने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) को राज्यों में नवीनतम अनुसंधान और डिज़ाइन पेटेंट कराने के लिए उद्यमियों को प्रेरित करने की नीति पर कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने 'शिक्षित अर्थव्यवस्था' की सोच के साथ काम करने पर जोर देते हुए कहा कि औद्योगिक विकास के लिए सरकार और उद्यमियों की साझा समझ विकसित किये जाने से ही देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ सकती है। मिश्र आज यहां भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा 'अनुसंधान विकास एवं नवाचारों के जरिये औद्योगिक विकास' विषयक राष्ट्रीय सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नवाचार अपनाते हुए उच्च विकास वृद्धि की रणनीति पर कार्य करना आज समय की जरूरत है। इसके लिए छोटे छोटे स्थानों पर होने वाले लोकल नवाचारों, डिज़ायन के नवीनतम रूपों और अनुसंधानों की पहचान कर उन्हें आगे लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देश में क्षमताओं की कमी नहीं है, पर एक राष्ट्रीय अनुसंधान और नवाचार प्रणाली के आवश्यक घटकों के विकास में औद्योगिक क्षेत्रों को आगे आकर कार्य करने की जरूरत है।

पटाखे बैन से व्यापारियों का दिवाली उत्साह पड़ा ठंडा, रोक से लाखों का नुकसान

नई दिल्ली:

दिल्ली में पटाखे जलाने पर पूरी तरह रोक लगाने के बाद व्यापारियों और दुकानदारों की दिवाली धुंआ हो गई है। व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने लाखों रुपए के पटाखों का स्टॉक दिवाली के लिए रखा था अब इस पर उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।

पटाखा व्यापारी परेशान

दिल्ली के जामा मस्जिद और सदर बाजार क्षेत्र के पटाखा व्यापारियों को इस बार दिवाली में अच्छी कमाई की उम्मीद थी। उन्होंने दिवाली, छठ पूजा, गुरुपर्व और आने वाले शादियों के मौसम के लिए पूरी तैयारियां कर रखी थीं। जामा मस्जिद के एक पटाखा व्यापारी ने कहा, ''पुलिस ने हमें दुकानें खोलने से रोक दिया है। हमने सैकड़ों किलो पटाखे खरीद कर रखे हैं। यह मौसम विशेष में बिकने वाला उत्पाद है, यदि एक-दो माह में इसे नहीं बेचा गया तो यह बेकार हो जाएगा।'

व्यापारियों ने बताया कि प्रशासन ने 650 किलो तक पटाखों के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किए थे। हालांकि, सामान्य तौर पर वह बाजार में मांग और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 400 से 500 किलो तक ही पटाखे खरीदकर रखते हैं। पटाखे बेचने का स्थायी लाइसेंस रखने वाले व्यापारी 1,000 किलो अथवा इससे अधिक स्टॉक अपने पास रख सकते हैं।

पटाखों की बिक्री पर रोक, बांटने पर नहीं

दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पटाखों के अस्थायी लाइसेंस के लिए कुल 260 आवेदन प्राप्त हुए थे। इसमें से सभी शर्तों को पूरा करने वाले 138 आवेदनों को लाइसेंस जारी किए गए। सदर बाजार पटाखा विक्रेता संघ के महासिचव हरदीप छाबड़ा ने कहा, ''मुझे नहीं पता कि मैं अपने पास रखे पटाखों के भंडार का अब क्या करूंगा, हो सकता है कि मैं इसे लोगों के बीच बांट दूं। पटाखों की बिक्री पर रोक लगी है उनको बांटने पर तो कोई रोक नहीं है।'

धरने पर बैठे पटाखा व्यापारी

छाबड़ा ने कहा कि पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने के सरकार के फैसले के खिलाफ पटाखा व्यापारी सदर बाजार में धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ समस्या का समाधान ढूंढने के लिए बैठक करने की भी योजना बनाई गई है। एक व्यापारी ने कहा, 'यदि सरकार की योजना पटाखे जलाने पर रोक लगाने की थी तो उसे पहले ही अपना फैसला सुना देना चाहिए था ताकि व्यापारी त्योहारी मौसम के लिए पटाखे खरीदकर नहीं रखते और हमें लाखों रुपये का नुकसान नहीं उठाना पड़ता।' दिल्ली सरकार ने राज्य में 30 नवंबर तक पटाखे जलाने पर रोक लगा दी। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में पटाखे जलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी। माना जा रहा है कि त्योहारी मौसम और बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं।

टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत, 31 मार्च तक उठाएं इस सरकारी स्कीम का फायदा

नई दिल्ली।

केंद्र सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स विवादों के निपटान के लिए लाई गई 'विवाद से विश्वास स्कीम' की समयसीमा को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। इस योजना को लाने का मकसद लंबित कर विवादों को हल करना है। इस योजना के तहत टैक्सपेयर्स को केवल विवादित टैक्स राशि का भुगतान करना होगा।

ब्याज और जुर्माने पर पूरी छूट

बता दें कि कोर्ट में प्रत्यक्ष कर से जुड़े 9.32 लाख करोड़ रुपए के करीब 4.83 लाख मामले लंबित पड़े हुए हैं। 'विवाद से विश्वास' स्कीम के लाने का मकसद लंबित कर विवादों का समाधान करना है। इस योजना के तहत करदाताओं को केवल विवादित टैक्स राशि का भुगतान करना होगा। उन्हें ब्याज और जुर्माने पर पूरी छूट मिलेगी। लेकिन शर्त के मुताबिक इन्हें इसका भुगतान 31 मार्च, 2021 तक करना होगा।

तीसरी बार योजना बढ़ाई गई

दरअसल, विवाद से विश्वास योजना 17 मार्च, 2020 को प्रभाव में आई थी। इससे पहले टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिये योजना के तहत घोषणा करने और भुगतान की समय सीमा 31 मार्च, 2020 से बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दी गई थी। बाद में इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2020 कर दिया गया था। पहले घोषणा और भुगतान दोनों 31 दिसंबर, 2020 तक किए जाने की जरूरत थी। अब तीसरी बार योजना के तहत भुगतान की समयसीमा बढ़ाई गई है।

जानें कौन उठा सकते हैं योजना का लाभ

बिल के मुताबिक, 31 जनवरी 2020 तक जो मामले कमिश्नर (अपील), इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लंबित थे, उन टैक्स के मामलों पर यह योजना लागू होगी। लंबित अपील टैक्स विवाद, पेनाल्टी या ब्याज से जुड़ी हो सकती है। एसेसमेंट या रीएसेसमेंट से भी इसका नाता हो सकता है।

गेल का दूसरी तिमाही मुनाफा नौ प्रतिशत घटा, गैस परिवहन कारोबार में हुआ नुकसान

नई दिल्ली।

देश की सबसे बड़ी गैस आपूर्ति करने वाली कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 8.5 प्रतिशत घट गया। कंपनी को गैस परिवहन कारोबार में नुकसान हुआ। गेल ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा है कि चालू वित्त वर्ष की जुलाई से सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ 1,068.16 करोड़ रुपये रहा है। प्रति शेयर लाभ 2.47 रुपये बैठता है। वहीं एक साल पहले इसी तिमाही का उसने 1,167.58 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया था। तब प्रति शेयर लाभ 2.59 रुपये रहा था। आलोच्य अवधि में गेल का कुल कारोबार 23.7 प्रतिशत घटक,.80 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इस दौरान गैस के दाम कम रहने के कारण कंपनी का कारोबार कम रहा। कंपनी को महामारी के कारण मांग प्रभावित होने की वजह से प्राकृतिक गैस के विपणन कारोबार में 334.55 करोड़ रुपये का कर पूर्व नुकसान हुआ। हालांकि, पहली तिमाही में उसका कर पूर्व नुकसान 614.06 करोड़ रुपये रहा था। एक साल पहले कंपनी को जुलाई- सितंबर तिमाही में 241.72 करोड़ रुपये का करपूर्व मुनाफा हुआ था। गेल ने कहा है, 'कोविड- 19 महामारी की वजह से दुनियाभर में और भारत में सामान्य कारोबारी गतिविधियों पर असर पड़ा और इससे आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ी।

कंपनी ने यह भी कहा है कि उसके भौतिक प्रदर्शन में अप्रैल-जून तिमाही के मुकाबले सुधार आया है और यह करीब करीब सामान्य स्तर पर पहुंच गई हैं।

दिवाली से पहले सस्ते हुए काजू-बादाम, फटाफट चेक करें नए रेट्स

बिजनेस डेस्कः

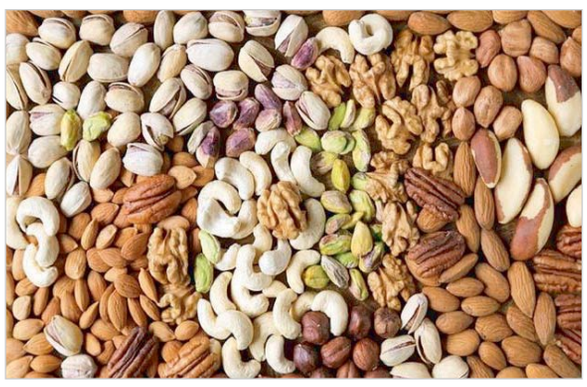

काजू-बादाम हो या फिर किशमिश और अखरोट, हर तरह की मेवा की नई फसल बाज़ार में आ चुकी है। बढ़िया फ्रेश माल की बाज़ार में कोई कमी नहीं है। बावजूद इसके मेवा बीते डेढ़ से दो महीने से सस्ती बनी हुई है। नई फसल आने के बाद भी अमेरिकन बादाम थोक में 525 रुपए किलो बना हुआ है।

अगर दो-तीन रुपए के मामूली उतार-चढ़ाव को छोड़ दें तो बादाम का यह रेट अक्टूबर से यही चला आ रहा है। यह हाल बादाम ही नहीं काजू-किशमिश और अखरोट का भी है। मेवा कारोबारियों को समझ नहीं आ रहा कि दिवाली जैसे त्योहार में भी मेवा के दामों में सुस्ती बनी हुई है।

जानिए नए रेट्स

मेवा कारोबारी राजीव बत्रा के अनुसार बादाम अमेरिकन 525 से 580 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा है। वहीं, काजू 660 से 710 रुपए प्रति किलोग्राम है।

किशमिश 200 से 230 रुपए प्रति किलोग्राम (किशमिश की कई वैराइटी होती हैं) इसके अलावा अखरोट की गिरी 800 से 850 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही हैं। छुहारा भी जनवरी के 300 रुपए प्रतिकिलो से घटकर अक्टूबर में 280 रुपए पर आ गया था। अब यह भी 260-270 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। पिस्ते का भाव 1150 से 1170 रुपए किलो के बीच चल रहा है। बाजार में पिस्ता का रेट 20 से 25 रुपए किलो के मामूली अंतर के साथ बिक रहा है।

भारत को नहीं मिलेगी फाइजर की कोरोना वैक्सीन! जानें क्या है देरी की वजह

नई दिल्ली-

कोरोना वैक्सीन को लेकर राहत भरी खबर है। फार्मा कंपनी फाइजर द्वारा बनाई गई कोरोना वैक्सीन क्लीनिकल ट्रायल में 90 प्रतिशत तक असरदायक पाई गई है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो नवंबर महीने के अंत तक कंपनी की वैक्सीन को बेचने की मंजूरी मिल जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, भारत को अभी इस वैक्सीन के लिए इंतजार करना होगा। फाइजर के अनुसार भारत ग्लोबल डील का हिस्सा नहीं है ऐसे में भारत से पहले वैक्सीन अमेरिका और अन्य देशों में जाएगी।

फाइजर के साथ अमेरिका का 10 करोड़ डोज के लिए करार

फाइजर के अनुसार इस वैक्सीन की शुरुआती डोज सबसे पहले अमेरिकी को दी जाएगी। अमेरिका ने पहले ही इसकी 10 करोड़ डोज खरीदने के लिए फाइजर के साथ करार कर लिया है। इसके अलावा वैक्सीन जिन देशों में पहले दी जाएगी उनमें कनाडा, जापान और ब्रिटेन जैसे देश हैं, जिन्होंने कंपनी से पहले ही करार किया हुआ है।

वैक्सीन को लेकर भारत में बना हुआ है संशय

कोरोना की इस वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर भारत में संशय बना हुआ है, क्योंकि यहां पर वैक्सीन को स्टोरेज की दिक्कत हो सकती है। इस वैक्सीन को खास कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। यह वैक्सीन -94 डिग्री फॉरेनहाइट से कम पर स्टोर होती है। यह वैक्सीन mRNA पर आधारित है, और इसी वजह से भारत में इसके इस्तेमाल को लेकर मुश्किलें आ सकती हैं।

Distribution के लिए चीन के साथ करार

फार्मा कंपनी फाइजर ने एशिया में Distribution के लिए चीन की कंपनी फोसून के साथ करार किया है।

खबरों की मानें तो भारत ने केवल फाइजर बल्कि वैक्सीन बनाने वाली किसी भी कंपनी के साथ एडवांस खरीद में किसी के साथ कोई समझौता नहीं किया है।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

एनबीए का 2020-21 सीजन 22 दिसंबर से शुरू होगा

न्यूयॉर्क । एनबीए का 2020-21 सीजन 22 दिसंबर से शुरू होगा और इसमें 72 मैच खेले जाएंगे। एनबीए और नेशनल बॉस्केटबॉल प्लेयर्स एसोसिएशन (एनबीपीए) ने घोषणा की है कि वे 2020-21 सीजन की शुरूआत को लेकर सैद्धांतिक रूप से एक समझौते पर पहुंच गए हैं। साथ ही कोविड-19 महामारी से प्रभावित होने के कारण सामूहिक करार के कुछ प्रावधानों में समायोजन किया गया है। एनबीए ने एक बयान में कहा, बास्केटबॉल से संबंधित आय (बीआरआई) पर पार्टियों की सहमति को सुनिश्चित करने के लिए एक नई प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। अगले दो सत्रों में किसी भी सीजन में अधिकतम 20 प्रतिशत वेतन कटौती होगी। फ्री एजेंट वार्ता 20 नवंबर को और करार के साथ यह 22 नवंबर को शुरू होगी। यह करार एनबीए के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा एक वोट के अधीन है।

लाइव स्पोर्ट्स में अमेजन प्राइम का प्रवेश, मिला एनजेडसी का इंडियन राइट्स

नई दिल्ली।

अमेजन प्राइम वीडियो ने मंगलवार को वर्ष 2025-26 तक न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए इंडियन टेरिटरी राइट्स के साथ भारत में लाइव स्पोर्ट्स में अपनी शुरूआत की घोषणा की।

इस घोषणा के साथ ही अमेजन प्राइम वीडियो एक प्रमुख क्रिकेट बोर्ड से एक्सक्लूसिव लाइव क्रिकेट राइट्स पाने वाली पहली इंडियन स्ट्रीमिंग सर्विस बन गई है।

अमेजन और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड (एनजेडसी) के बीच हुए इस करार के तहत प्राइम वीडियो 2021 के अंत से न्यूजीलैंड में खेले जाने वाले पुरुषों और महिला के सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जैसे कि वनडे, टी-20 और टेस्ट के लिए वन-स्टॉप स्ट्रीमिंग डेस्टिनेशन बन जाएगा। करार में 2022 की शुरूआत में टीम इंडिया का न्यूजीलैंड दौरा और दूसरा दौरा, जिसकी तारीखों की घोषणा बाकी है, यह सब शामिल है। इस महीने के अंत में शुरू होने वाले 2020-2021 सीजन के राइट्स को अमेजॅन द्वारा सिंडिकेटेड किया जाएगा। अमेजन प्राइम वीडियो के निदेशक और कन्ट्री जनरल मैनेजर गौरव गांधी ने कहा, पिछले कुछ वर्षो में अमेजॅन प्राइम वीडियो भारत में विश्व स्तर के मनोरंजन के लिए पहचान बनाने वाला प्लेटफॉर्म बन गया है, जिसमें हमारी अमेजॅन सीरीज और विभिन्न भाषाओं में सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं। हम अपने प्राइम वीडियो ग्राहकों के लिए हमारे कंटेंट के चयन के लिए भारत के सबसे प्रिय खेल क्रिकेट को जोड़ने के लिए उत्साहित हैं। हम इस प्रयास में न्यूजीलैंड क्रिकेट के साथ काम करने के लिए रोमांचित हैं क्योंकि उनके पास एक मजबूत, भावुक और बहुत-पसंद क्रिकेट टीम है और दोनों देशों के बीच क्रिकेट की प्रतिद्वंद्विता शानदार रही है। हमें न्यूजीलैंड क्रिकेट के साथ मिलकर भारत में हमारी पहली लाइव स्पोर्ट की पेशकश करते हुए खुशी हो रही है और हमें विश्वास है कि हमारे प्राइम सदस्य इस पहल से प्रसन्न होंगे।

न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुख्य कार्यकारी डेविड व्हाइट ने कहा, अमेजॅन प्राइम वीडियो के साथ यह साझेदारी न्यूजीलैंड के लिए बहुत बड़ी है। हम इस तरह के एक प्रसिद्ध और सफल ब्रांड के साथ मिलकर खुश और गर्व महसूस कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले कहा था कि लाइव स्पोर्ट का भविष्य स्ट्रीमिंग है और अमेजॅन प्राइम वीडियो में हमारे पास इंडस्ट्री के पार्टनर राइट है, जो प्रशंसकों और ग्राहकों को सबसे पहले रखने के लिए अभिनव, ट्रेंड-सेटर और प्रसिद्ध है।

आस्ट्रेलिया बनाम भारत : दिन-रात टेस्ट में प्रति दिन 27,000 दर्शकों की होगी मंजूरी

मेलबर्न। भारत और आस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड ओवल में होने वाले बॉर्डर-गावस्कर टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मैच में प्रति दिन 27,000 दर्शकों को स्टेडियम में आने की मंजूरी होगी जो स्टेडियम की पूरी तादाद से आधी है। यह फैसला कोविड-19 माहमारी के कारण लिया गया है। दिन-रात का यह टेस्ट मैच 17 से 21 दिसंबर के बीच एडिलेड में खेला जाएगा। यह इस दौरे पर वो इकलौता टेस्ट मैच होगा जिसमें विराट कोहली हिस्सा लेंगे। इसके बाद वह अपने पहले बच्चे के जन्म के कारण स्वदेश लौट आएंगे। एडिलेड टेस्ट भारत और आस्ट्रेलिय के बीच पहला दिन-रात का टेस्ट मैच होगा। अभी तक दोनों में से कोई भी टीम दिन-रात का टेस्ट मैच नहीं हारी है। आस्ट्रेलिया ने अभी तक चार दिन-रात के टेस्ट मैच खेले हैं और सभी में जीत हासिल की है। वहीं भारत ने अभी तक सिर्फ एक दिन-रात का टेस्ट मैच पिछले साल बांग्लादेश के खिलाफ ईडन गार्डन्स में खेला था जिसमें वो जीती थी। टेस्ट सीरीज से पहले भारत और आस्ट्रेलिया तीन मैचों की वनडे और टी-20 सीरीज भी खेलेगी। क्रिकेट आस्ट्रेलिया ने एक आधिकारिक बयान में कहा, 'सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (एससीजी) वनडे और टी-20 मैचों की मेजबानी करेगा। गुलाबी गेंद से होने वाले टेस्ट मैच में 50 प्रतिशत दर्शक मौजूद रहेंगे। कैनबरा के मनुका ओवल में होने वाले वनडे और टी-20 मैचों में भी स्टेडियम की तादाद के मुताबिक 50 प्रतिशत दर्शक ही मैच देखने आ सकेंगे।' मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होने वाले बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में विक्टोरिया सरकार ने प्रति दिन 25,000 दर्शकों की ही मंजूरी दी है। गाबा में होने वाले चौथे और आखिरी टेस्ट मैच में 75 प्रतिशतक दर्शक प्रति दिन मैच देखने आ सकेंगे। सीए ने कहा, 'अभी की स्थिति के मुताबिक बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में 25 प्रतिशत दर्शक हर दिन मैच देखने के लिए आ सकेंगे। इन 25 प्रतिशत टिकटों में पब्लिक, सदस्य, कॉरपोरेट टिकट सभी शामिल हैं। गाबा अपनी तादाद के मुताबिक 75 प्रतिशत दर्शकों की मेजबानी करेगा।' तीन मैचों की वनडे सीरीज के दो मैच एससीजी में 27, 29 नवंबर को खेले जाएंगे जबकि तीसरा मैच 2 दिसंबर को मनुका ओवल में खेला जाएगा। तीन मैचों की टी-20 सीरीज का पहला मैच मनुका ओवल पर चार दिसंबर को बाकी के बचे दो मैच एससीजी पर छह और आठ दिसंबर को खेले जाएंगे।

एटीपी रैंकिंग : रामनाथन की 21 स्थान की छलांग, नागल 2 स्थान गिरे

नई दिल्ली ।

भारत के टेनिस खिलाड़ी रामकुमार रामनाथन 21 स्थान की लम्बी छलांग के साथ ताजा एटीपी रैंकिंग में टॉप 200 में शामिल हो गए हैं जबकि सुमित नागल दो स्थान गिर गए हैं। सोमवार को जारी रैंकिंग में रामनाथन 21 स्थान की छलांग के साथ 185वें स्थान पर पहुंच गए हैं। भारत के शीर्ष एकल खिलाड़ी नागल रैंकिंग में दो स्थान की गिरावट के साथ 135वें नंबर पर खिसक गए हैं जबकि प्रजनेश गुणेश्वरन का 146वां स्थान बरकरार है। पेरिस मास्टर्स के पुरुष युगल के क्वार्टरफाइनल तक पहुंचने वाले रोहन बोपन्ना का 39वां स्थान बना हुआ है। दिविज शरण भी 63वें स्थान पर बरकरार हैं।

बीसीसीआई ने चयनकर्ताओं के लिए मांगे आवेदन, आयु सीमा ने आलोचकों को रखा बाहर

नई दिल्ली।

बीसीसीआई ने तीन नए चयनकर्ताओं के लिए आवेदन मांगे हैं जो मौजूदा राष्ट्रीय चयन समिति में सरनदीप सिंह, जतिन प्रांजपे और देवांग गांधी का स्थान लेंगे। इन तीनों का कार्यकाल सितंबर में समाप्त हो गया है। बीसीसीआई हालांकि आवेदन मांगने की प्रक्रिया में अपने ही संविधान से आगे चली गई और उसने चयनकर्ताओं की आयु सीमा 60 वर्ष ही मांगी है। इसने भारत के पूर्व कप्तान दिलीप वेंगसरकर को रेस से बाहर रखा है जो हाल ही में बीसीसीआई की लगातार आलोचना करते आ रहे हैं। वेंगसरकर हालांकि 2007 से 2008 तक मुख्य चयनकर्ता रह चुके हैं। बीसीसीआई के संविधान के मुताबिक उसकी किसी भी समिति की सीमा, जिसमें राष्ट्रीय चयन समिति भी शामिल है,पांच साल है जबकि बीसीसीआई की मौजूदा चयन समिति में चयनकर्ताओं का कार्यकाल चार साल का है। बीसीसीआई के नियमों के मुताबिक उम्र संबंधी सीमा 70 साल की है। बीसीसीआई के संविधान के नियम 6 (5) (बी) के मुताबिक वो शख्स जिसकी उम्र 70 साल या उससे ज्यादा है वो बोर्ड की किसी भी समिति का सदस्य नहीं बन सकता। वेंगसरकर ने हाल ही में बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली की यह कहते हुए आलोचना की थी कि वह कई सारे काम खुद ही कर रहे हैं और मुख्य चयनकर्ता सुनील जोशी की तरफ से बयान दे रहे हैं। बीसीसीआई ने सरनदीप, जतिन, गांधी के कार्यकाल को सितंबर के बाद भी जारी रखने की मंजूरी दे दी थी और इन्हीं ने आस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम का चयन भी किया। इन तीनों ने 21 सितंबर, 2016 को चयनसमिति में कदम रखा और उसी दिन इन तीनों को चार साल बाद कार्यकाल पूरा करने के बाद अपने पद छोड़ने थे। विज्ञापन में चयनकर्ताओं के लिए पैमाना हालांकि संविधान के मुताबिक है। विज्ञापन के मुताबिक, खिलाड़ी ने कम से कम सात टेस्ट मैच, और 30 प्रथम श्रेणी मैच, और 10 वनडे, और 20 प्रथम श्रेणी मैच और पांच साल पहले खेल से संन्यास लिया होना चाहिए। आवेदन 15 नवंबर, 2020 को शाम छह बजे तक जमा कराने होंगे। उसके बाद शॉर्टलिस्ट कर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। गांगुली ने हालांकि अभी तक आईएएनएस के सवालों का जवाब नहीं दिया है।

संक्षिप्त समाचार

अगले साल की शुरूआत में हो सकते हैं ओलंपिक टेस्ट टूर्नामेंट

टोक्यो ÷ पिछले सप्ताह हुई जिम्नास्टिक स्पर्धा से उत्साहित टोक्यो ओलंपिक के आयोजकों ने मंगलवार को कहा कि वे ओलंपिक टेस्ट टूर्नामेंट अगले साल की शुरूआत में कराने को तैयार हैं। रविवार को हुई जिम्नास्टिक स्पर्धा में 22 रूसी, चीनी और अमेरिकी खिलाड़ियों ने भाग लिया था। कई हजार दर्शक भी इसे देखने के लिये मौजूद थे। टोक्यो ओलंपिक के 'गेम्स डिलीवरी % अधिकारी हाइडमासा नकामूरा ने आनलाइन कांफ्रेंस में कहा कि वे मार्च में और टेस्ट टूर्नामेंट कराने की सोच रहे हैं। उन्होंने यह नहीं बताया कि ये किस रूप में होंगे और क्या इनमें जापान से इतर देशों के खिलाड़ी भी भाग ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि हम बात कर रहे हैं कि जापान सरकार और तोक्यो महानगर प्रशासन के साथ मिलकर कोरोना वायरस महामारी से कैसे निपटा जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगले साल की शुरूआत से हम काम शुरू कर देंगे और मार्च में टेस्ट टूर्नामेंट होंगे। कोरोना महामारी के कारण तोक्यो ओलंपिक पिछले साल स्थगित कर दिए गए थे ।

मोटो जीपी-2020 सीजन के बाकी सत्र में नहीं होंगे मारक्वेज

मेड्रिड। छह बार के मोटो जीपी विश्व विजेता मार्क मारक्वेज 2020 के बाकी सीजन में नहीं उतरेंगे। वह अपने टूटे हाथ को ठीक करने में लगे हुए हैं। रेप्सोल होंडा ने मंगलवार को इस बात की पुष्टि की। सीजन में अभी दो रेसें बची हैं और इसलिए होंडा ने मारक्वेज के छोटे भाई एलेक्स और टेस्ट राइडर स्टेफन ब्राडल के साथ जाने का फैसला किया है। जुलाई में स्पेनिश ग्रां प्री में मारक्वेज अपना हाथ चोटिल करा बैठे थे। जेरेज में दूसरी रेस से पहले उनकी सर्जरी हुई थी। स्पेन के इस रेसर ने मंगलवार को ट्वीट करते हुए बताया, इस सीजन मैं दोबारा प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टर से हाथ को लेकर चर्चा के बाद मेरी टीम ने फैसला किया है कि सबसे उपयुक्त विकल्प अगले साल लौटना ही है। यह समय है कि रिकवरी जारी रखी जाए। समर्थन के संदेशों के लिए शुक्रिया। 2021 में वापसी के लिए तैयार।

पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को आठ विकेट से हराया, टी20 श्रृंखला में क्लीन स्वीप किया

रावलपिंडी :

पाकिस्तान ने मंगलवार को यहां एल्टन चिगुम्बुरा के विदाई अंतरराष्ट्रीय मैच में जिम्बाब्वे को आठ विकेट से हराकर ट्वेंटी20 श्रृंखला में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। चिगुम्बुरा (34 वर्ष) जब अंतिम बार बल्लेबाजी के लिये उतरे तो उन्हें पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया। हालांकि जिम्बाब्वे का यह अनुभवी बल्लेबाज केवल चार गेंद ही खेल सका और दो रन बनाकर आउट हो गया। जिम्बाब्वे ने नौ विकेट गंवाकर 129 रन का स्कोर बनाया। लेग स्पिनर उस्मान कादिर ने 13 रन देकर चार विकेट चटकाये जिससे उन्होंने अपनी पदार्पण श्रृंखला में आठ विकेट हासिल किए। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के कमजोर गेंदबाजी आक्रमण के सामने 15.2 ओवर में दो विकेट पर 130 रन बनाकर जीत हासिल की। कप्तान बाबर आजम से पहले सलामी बल्लेबाज के तौर पर पदार्पण करने वाले अब्दुल्लाह शफीक ने नाबाद 41 रन जबकि चौथा टी20 मैच खेल रहे खुशदिल शाह ने 15 गेंद में तीन चौके और तीन छक्के से नाबाद 30 रन बनाए।

केएआई ने यशपाल कल्सी को स्पोर्टस कमिशन चेयरमैन नियुक्त किया

नई दिल्ली।

भारतीय कराटे संघ (केएआई) ने यशपाल सिंह कल्सी को अपना नया स्पोर्टस कमिशन चेयरमैन नियुक्त किया है। केआई ने हाल ही में 23 अक्टूबर को अपने चुनाव गुवाहाटी में कराए थे। कल्सी ने एक बयान में कहा, केएआई ने कई तरह से मेरे जीवन में अहम रोल निभाया है। मेरे लिए स्पोर्टस कमिशन चेयरमैन नियुक्त किया जाना सम्मान की बात है। उन्होंने कहा, मैं खुद अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहा हूं और मुझे कोच के तौर पर भी अनुभव है, इसलिए मुझे लगता है कि भारत में कराटे के बेहतर माहौल के लिए सही जानकारी दूंगा। चेयरमैन नियुक्त किए जाने पर केआई का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। विश्व कराटे महासंघ से सर्टिफाइड कोच कल्सी को सातवीं डैन में ब्लैक बेल्ट मिला है। उनके पास मार्शल आर्टस में खिलाड़ी के तौर पर 30 साल का और कोच के तौर पर 25 साल का अनुभव है। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियंस को कोचिंग दी है। वह भारतीय टीम के लिए खेले हैं और हाल ही में उनके शिष्यों ने 2019 में नीदरलैंड्स में आयोजित किए गए रोटरडैम कप में परचम लहराया था। अपने पेशेवर करियर में उन्होंने अमेरिका ओपन कराटे चैम्पियनशिप-2016 में स्वर्ण पदक जीता था। इसी चैम्पियनशिप में उन्होंने 2017 में दो कांस्य पदक भी जीते थे।

बांग्लादेश के टेस्ट कप्तान मोमीनुल हक कोरोना पॉजिटिव

ढाका। बांग्लादेश के टेस्ट कप्तान मोमीनुल हक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, हक इस समय खुद को घर में क्वारंटाइन किए हुए हैं। हाल में उनके अंदर हल्का सा लक्षण दिखाई दिया था और फिर इसके बार जब उन्होंने टेस्ट करवाया तो वो पॉजिटिव पाए गए। बांग्लादेश के लिए अब तक 40 टेस्ट, 28 वनडे और छह टी-20 मैच खेलने वाले हक का अब आगामी बंगबंधु टी-20 टूर्नामेंट में खेलना तय नहीं माना जा रहा है। इससे पहले, बांग्लादेश टी-20 क्रिकेट टीम के कप्तान महमुदुल्लाह कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे। महमुदुल्लाह अब पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) के प्लेऑफ में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। महमुदुल्लाह और तमीम इकबाल को पीएसएल के पांचवें संस्करण के प्लेऑफ में खेलना था जो 14 नवंबर से शुरू हो कर 17 नवंबर तक चलेंगे। मुल्तान सुल्तांस ने महमुदुल्लाह को मोइन अली की जगह टीम में शामिल किया था वहीं लाहौर कलंदर्स ने तमीम की जगह क्रिस लिन को टीम में शामिल किया था।

बलुई मैदान भारतीय खिलाड़ियों के हैमस्ट्रिंग के लिए अहम

नई दिल्ली।

आईपीएल-13 टूर्नामेंट में अब तक कम से कम पांच भारतीय खिलाड़ी हैमस्ट्रिंग चोट का शिकार हो चुके हैं और इनमें टीम इंडिया के सीमित ओवरों के उपकप्तान रोहित शर्मा भी शामिल हैं। इसका एक कारण तो कोविड-19 के कारण लंबे समय के बाद क्रिकेट खेलना और दूसरा कारण संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की बलुई मैदान (मिट्टी और बालू के मिश्रण वाले) हैं। रोहित के अलावा रिद्धिमान साहा, विजय शंकर, अंबाती रायडू और ऋषभ पंत अब तक हैमस्ट्रिंग और खिंचाव का शिकार हो चुके हैं। भुवनेश्वर कुमार तो जांघ में खिंचाव के कारण टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए थे। इन पांच में से तीन खिलाड़ियों को आस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम में चुना गया है। पूर्व क्रिकेटर और अब कमेंटेटर मुरली कार्तिक ने भी पिछले सप्ताह एक मैच के दौरान कहा था, टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के चोटिल होने का कारण बलुई मैदान है। यूएई में शारजाह, दुबई और अबू धाबी के मैदान बालू और मिट्टी के मिश्रण से बने हुए हैं, जोकि काफी नरम हैं और इससे खिलाड़ी अधिक हैमस्ट्रिंग के शिकार होते हैं। यह पहली बार है कि आईपीएल का पूरा सीजन यूएई में खेला जा रहा है। इससे पहले, 2014 में बीसीसीआई ने केवल 20 मैच ही यूएई में करवाए थे। भारत में, कई मैदान मिश्रित मिट्टी से मिलकर बना है और केवल अच्छी रेत से इसकी ड्रेसिंग की गई है। बीसीसीआई के पूर्व पिच क्यूरेटर दलजीत सिंह ने कहा, मिट्टी के मैदान की तुलना में बलुई मैदान काफी नरम होते हैं। भारत में, बनाए जा रहे सभी नए स्टेडियमों में बालू युक्त आउटफील्ड होता है क्योंकि इनमें पानी तेजी से निकलता है और घास भी बेहतर तरीके से उगता है और इनकी सिंचाई भी बेहतर होती है। पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर सिंह ने कहा, मिट्टी के मैदानों पर आउटफील्ड कठिन और असंगत है। किसी स्थान पर घास या भूरे रंग का एक पैच होगा। खिलाड़ियों के स्पाइक्स नहीं होते हैं। वे केवल गहरी और सतह वाली पिचों को पसंद करेंगे। भारत में, ईडन गार्डन्स, वानखेड़े स्टेडियम, फिरोजशाह कोटला या मोहाली जैसे पुराने मैदान मिट्टी के मैदान है जबकि मुलनपुर में बना पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का नया मैदान पूरी तरह से बलुई है।

मेलबर्न रेनेगेड्स ने रिले रॉसौव के साथ किया करार

मेलबर्न। मेलबर्न रेनेगेड्स ने बिग बैश लीग (बीबीएल) के आगामी सीजन के लिए दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज रिले रॉसौव के साथ करार करने की घोषणा की है। रॉसौव पूरे सीजन के लिए टीम से जुड़े हैं। उनसे पहले मोहम्मद नबी, नूर अहमद और इमरान ताहिर रेनेगेड्स से जुड़ने वाले विदेशी खिलाड़ी हैं। रॉसौव ने कहा, ÷बिश बैश लंबे समय से उच्च स्तरीय प्रतियोगिता रहा है, इसलिए मैं इस तरह की प्रतिस्पर्धात्मक लीग से जुड़ने के लिए उत्साहित हूं।÷ नूर अहमद बीबीएल के शुरुआती मैचों में रेनेगेड्स के लिए खेलेंगे जबकि ताहिर क्रिसमस के बाद टीम से जुड़ेंगे। बीबीएल के इस सीजन में रेनेगेड्स को अपना पहला मुकाबला 12 दिसंबर को होबार्ट में पर्थ स्कॉचर्स के साथ खेलना है। मेलबर्न रेनेगेड्स टीम = नूर अहमद, कैमरन बॉएस, जेक इवांस, एरॉन फिंच (कप्तान), जेक फ्रेजर-मैकगर्क, सैम हैपर, मार्कस हैरिस, मैकेंजी हार्वे, जॉन हॉलैंड, जोश लालोर, शॉन मार्श, मोहम्मद नबी, जेम्स पैटिंसन, मिच पेरी, जैक प्रेस्टिज, केन रिचर्डसन, रीली रॉसौव, विल सदरलैंड, इमरान ताहिर, ब्यू वेबस्टर।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

मल्लिका शेरावत ने 11 साल पहले एक ट्वीट किया था. उन्होंने जब यह ट्वीट किया था कमला हैरिस उस समय सैन फ्रांसिस्को की जिला अटॉर्नीथीं. एक्ट्रेस ने इस ट्वीट में कमला हैरिस के एक दिन अमेरिकी राष्ट्रपति हो बनने की भविष्यवाणी की थी.

मल्लिका शेरावत ने कमला हैरिस को लेकर 2009 में किया था ये ट्वीट, बता दिया था भविष्य

दुनिया इन दिनों कमला हैरिसकी जीत का जश्न मना रही है. भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति के रूप में चुनी जाने वाली पहली महिला हैं. कमला हैरिस की जीत पर तमाम लोगों सहित बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी उन्हें बधाई दे रहे हैं. हालांकि, एक ऐसी भी एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने कमला हैरिस के भविष्य को लेकर 2009 में ही ऐसा कुछ कहा था, जो अब काफी तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. ये एक्ट्रेस हैं मल्लिका शेरावत .

दरअसल, मल्लिका शेरावत ने 11 साल पहले एक ट्वीट किया था. उन्होंने जब यह ट्वीट किया था कमला हैरिसउस समय सैन फ्रांसिस्को की जिला अटॉर्नी थीं. एक्ट्रेस ने इस ट्वीट में कमला हैरिस के एक दिन अमेरिकी राष्ट्रपति हो बनने की भविष्यवाणी की थी. उनका यह ट्वीट अब यूजर्स ने खोज निकाला है और यह अब खूब वायरल हो रहा है.

इस ट्वीट में मल्लिका शेरावत 23 जून 2009 में किया था. जिसमें उन्होंने लिखा था- एक फैंसी कार्यक्रम में एक महिला के साथ मस्ती करना, जिसे वह कहते थे कि वह यूएस की राष्ट्रपति हो सकती हैं. कमला हैरिस. मल्लिका शेरावत के इस ट्वीट से हर कोई हैरान है. लोग उनके इस ट्वीट को लेकर उनकी तुलना जोफ्रा आर्चर से कर रहे हैं.

एक यूजर ने मल्लिका शेरावत के इस ट्वीट को लेकर लिखा है- आप तो औरतों की जोफ्रा आर्चर हैं. दरअसल, जोफ्रा आर्चर ने 6 साल पहले एक ऐसा ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने सिर्फ जो शब्द लिखा था. अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के दौरान जोफ्रा आर्चर का यह ट्वीट काफी वायरल हुआ था.

1950 के अवतार में नजर आई जाह्नवी कपूर, फैन्स बोले- क्लासिक

जाह्नवी कपूर बॉलीवुड की पॉप्युलर स्टार डॉटर्स में से एक हैं। वह अकसर खुद की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती हैं। इन दिनों जाह्नवी कपूर के रेट्रो लुक वाली फोटोज तेजी से वायरल हो रही हैं। जाह्नवी ने अलग-अलग तरह की साड़ी पहनकर फोटोशूट कराया है। फैन्स भी उनके इस लुक की तारीफ कर रहे हैं।

फोटो शेयर करते हुए जाह्नवी कपूर लिखती हैं, 1950 के लुक में रहने की कोशिश कर रही हूं, वह भी एक दिन के लिए। काफी मजा आया। जाह्नवी कपूर की इन फोटोज पर कई बॉलीवुड सेलेब्स ने कॉमेंट किए। अथिया शेट्टी ने आंख में हार्ट इमोजी वाली स्माइली पोस्ट की। वहीं, दीया मिर्जा ने 'बेहद खूबसूरत' लिखा।

बता दें कि इससे पहले जाह्नवी कपूर ने डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के ब्राइडल लहंगे पहनकर फोटोशूट कराया था। घूंघट और हैवी जूलरी के साथ मेहंदी भरे हाथों में धड़क एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर का लुक और अंदाज देखने लायक रहा था। जाह्नवी ने अपने ब्राइडल लुक की तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। उन्होंने लिखा था- क्या आपको शहनाई की आवाज सुनाई दे रही या सिर्फ मुझे ही मनीष मल्होत्रा के नए कलेक्शन का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूं।

जाह्नवी कपूर को आखिरी बार गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में देखा गया था। फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आई थी। वहीं, जाह्नवी की अपकमिंग फिल्म्स किटी, दोस्ताना-2 और तख्त हैं।

मालदीव में बिना मेकअप कैटरीना कैफ ने कराया फोटोशूट, आलिया भट्ट का कॉमेंट जीत लेगा दिल

बॉलीवुड की 'बार्बी गर्ल' कैटरीना कैफ किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस मालदीव पहुंची हैं, लेकिन वेकेशन के लिए नहीं फोटोशूट के लिए। जी हां, कैटरीना कैफ ने समुद्र किनारे अपनी दो फोटोज शेयर की हैं, जिसमें उन्हें व्हाइट और मल्टी कलर टॉप पहने देखा जा सकता है। कैटरीना ने यह जानकारी खुद फैन्स को दी है।

फोटो शेयर करते हुए कैटरीना लिखती हैं, बहुत शानदार लगता है जब मैं मालदीव में होती हूं, वह भी फोटोशूट के लिए। तभी तो मैं अपने काम से प्यार करती हूं। इसपर आलिया भट्ट समेत कई सेलेब्स ने कॉमेंट किया है। आलिया भट्ट लिखती हैं, खूबसूरत।

बता दें कि कैटरीना कैफ ने लॉकडाउन का पूरा समय बहन इजाबेल कैफ संग बिताया। इसके साथ ही उन्होंने घर का काम करते हुए के वीडियो और फोटोज भी शेयर किए। इसके अलावा कैटरीना दोस्त विक्की कौशल संग भी कई बार स्पॉट की गईं। बॉलीवुड गलियारों में दोनों के अफेयर के चर्चे भी खूब जोर पकड़ रहे हैं।

कैटरीना कैफ जल्द ही रोहित शेट्टी की फिल्म 'सूर्यवंशी' में नजर आएंगी। यह फिल्म थिएटर्स में रिलीज के लिए तैयार है। वहीं, कैटरीना इस समय फिल्म 'फोन भूत' की शूटिंग शुरू करने वाली हैं।

ब्लू बिकिनी में कहर ढा रही हैं कश्मीरा शाह, फैन्स कर रहे जमकर तारीफ

एक्ट्रेस कश्मीरा शाह आजकल सुर्खियों में हैं। दरअसल, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इंटरनेट पर इन्होंने तहलका मचाया हुआ है। कश्मीरा ने 10 किलो वजन कम कर लिया है। शेप में आने के बाद वह अपनी बॉडी फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर लगातार फोटोज और वीडियोज शेयर कर कर रही हैं।

हाल ही में कश्मीरा ने ब्लू बिकिनी में फोटोशूट कराया है। स्विमिंग पूल किनारे बैठीं कश्मीरा शाह एक से बढ़कर एक पोज दे रही हैं। ब्लू बिकिनी के ऊपर उन्होंने मल्टी कलर सुरोस्की कोट पहना हुआ है। स्मोकी आइज और न्यूड लिपस्टिक के साथ मेकअप किया हुआ है। फोटो शेयर करते हुए कश्मीरा ने लिखा, बदलाव की शुरुआत खुद से करें। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो पहले खुद में बदलाव लाएं।

कश्मीरा के इस अंदाज की फैन्स सराहना कर रहे हैं। फोटोज पर कॉमेंट कर उनकी तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, बेहद खतरनाक फोटोज। वहीं, एक और यूजर लिखते हैं, हमेशा ही खूबसूरत।

बता दें कि इससे पहले कश्मीरा की ब्लैक मोनोकिनी में फोटो वायरल हुई थी।

पति कृष्णा अभिषेक ने भी उनकी इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा था, जब आपके पास घर पर बिरयानी हो तो बाहर दाल मखनी क्यों खानी है कैश मुझे तुमपर गर्व है, क्योंकि तुम अपने हॉट अवतार में वापस आ गई हो।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

ब्राजील ने चौंकाते हुए अचानक कोविड -19 की चीनी टीके का परीक्षण रोका

एजेंसी, साओ पाउलो। ब्राजील के स्वास्थ्य नियामक ने प्रतिकूल और गंभीर प्रभाव वाली घटना के मद्देनजर कोरोना वायरस के संभावित चीनी टीके 'कोरोनावैक का चिकित्सकीय परीक्षण रोक दिया है। फैसले की सूचना सोमवार रात को ब्राजीली स्वास्थ्य नियामक एनविजा की वेबसाइट पर दी गई। इससे टीके के उत्पादन में शामिल पक्ष भी आश्चर्यचकित हैं। कोविड-19 के इस संभावित टीके को चीनी फार्मास्युटिकल कंपनी साइनोवैक ने विकसित किया और ब्राजील में इसका ज्यायदातर उत्पादन साओ पाउलो स्थित सरकारी संस्थान बुटानटैन इंस्टीट्यूट करेगा।

साओ पाउलो की प्रांतीय सरकार ने एक बयान में कहा कि उसे ' 'खेद है कि उसे इसकी सूचना एनविजा से सीधे नहीं बल्कि प्रेस से मिली, जैसा सामान्य तौर पर इस प्रकृति के चिकित्सकीय परीक्षण में होता है। बुटानटैन ने एक बयान में कहा कि वह एनविजा के फैसले से स्तब्ध है और मंगलवार को इस मामले में संवाददाता सम्मेलन करेगा। उल्लेखनीय है कि कोरोनावैक को लेकर ब्राजील में पहले ही विवाद है और स्वयं राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो ने इसके रक्षात्मक प्रभाव को लेकर आशंका प्रकट की है। यह परीक्षण ऐसे समय रोका गया है जब

साओ पाउलो कोरोनावैक की 40 करोड़ खुराक बनाने के लिए कच्चा माल आयात कर रहा है और 27 नवंबर से देश में इसकी खेप पहुंचनी शुरू हो जाएगी।

शंघाई हवाई अड्डे का कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित, 8000 से ज्यादा जांच

बीजिंग। चीन का वित्तीय केंद्र कहे जाने वाले शंघाई के मुख्य अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक कर्मचारी के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद 186 लोगों को पृथक-वास में रखा गया और 8,000 से ज्यादा लोगों की जांच की गई। शहर की सरकार ने मंगलवार को बताया कि इसके अलावा कोई और व्यक्ति संक्रमित नहीं मिला है। 51 वर्षीय कर्मचारी कैसे संक्रमित हुआ। वहीं उत्तरी बंदरगाह शहर तियानजीन में स्थानीय संक्रमण का एक मामला सामने आने के बाद 77,000 से ज्यादा लोगों की जांच की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशासन ने मंगलवार को बताया कि विदेश से आने वाले 21 और लोग संक्रमित पाए गए, वहीं 426 लोगों का इलाज चल रहा है। चीन में इस वायरस के 86,267 मामले सामने आये है जिनमें से 4,634 लोगों की मौत हो चुकी हैं।

अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर का दावा, तीसरे चरण के ट्रायल में कोरोना वैक्सीन 90 फीसदी से ज्यादा प्रभावी

नई दिल्ली। अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर जर्मन बायोटेन फर्म बायोएनटेक द्वारा संयुक्त रूप से विकसित वैक्सीन तीसरे चरण में 90 फीसदी से अधिक प्रभावी साबित हुई है। शुरुआत निष्कर्षों से पता चला है कि पहली बार डोज दिए जाने के 28 दिनों बाद और दूसरे बार दो खुराक दिए जाने के 7 दिन बाद मरीज को सुरक्षा प्राप्त हुई है। फाइजर के अध्यक्ष और सीईओ अल्बर्ट बोरला ने एक बयान में कहा कि हमारे तीसरे चरण के ट्रायल के पहले सेट में कुछ ऐसे सबूत मिलने है दूसरी आस्ट्रेलिया की सीएसएल लिमिटेड कंपनी ने सोमवार को ऑक्सफोर्ड/एस्ट्राजेनेका यूनिवर्सिटी के कोरोना वायरस वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर दिया है। सिडनी के 2जीबी रेडियो के अनुसार आज विक्टोरिया में वैक्सीन की तीन करोड़ खुराक के उत्पादन के दायरे में पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हुंट ने 2जीओ को कहा, वैक्सीन स्वेच्छा से लगाया जा रहा है, लेकिन हम अधिक से अधिक लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे। हमें विश्वास है कि ऑस्ट्रेलियाई जनसंख्या के हिसाब से हमारे पास बहुत अधिक वैक्सीन है।

राहत : ऑस्ट्रेलिया में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन की तीन करोड़ खुराक तैयार

एजेंसी, कैनबरा। कोरोना महामारी से जूझ रही दुनिया के लिए ऑस्ट्रेलिया से बड़ी राहत और उम्मीद भरी खबर आई है। ऑस्ट्रेलिया की सीएसएल लिमिटेड कंपनी ने ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका की कोरोना वायरस वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने दावा किया कि सोमवार तक कंपनी विक्टोरिया में वैक्सीन की तीन करोड़ खुराक के उत्पादन के दायरे में पहुंच गई है। सिडनी के 2-जीबी रेडियो के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हुंट ने इसकी पुष्टि की है। हंट ने 2-जीबी रेडियो को कहा, ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से टीकाकरण स्वेच्छिक होगा।

स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक मार्च में आम लोगों को इसकी खुराक मिलनी शुरू हो जाएगी। वहीं, सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड अखबार ने बताया कि टीके को पूरी तरह से संसाधित करने में सीएसएल को लगभग 50 दिन लगेंगे। अखबार के मुताबिक, वैक्सीन के उत्पादन के लिए कंपनी का एस्ट्राजेनेका और ऑस्ट्रेलियाई सरकार के साथ अलग-अलग अनुबंध है।

ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को अभी भी ऑस्ट्रेलिया के चिकित्सीय प्रशासन द्वारा स्वीकृति दिए जाने की जरूरत है। इस वर्ष के अंत तक वैक्सीन के तीसरे चरण का चिकित्सकीय परीक्षण पूरा होने की उम्मीद है।

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच यूरोप में आईसीयू बिस्तरों और स्वास्थ्यकर्मियों की कमी

पेरिस। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहे यूरोपीय देशों में आईसीयू बिस्तरों और स्वास्थ्यकर्मियों की कमी हो रही है। इटली के अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंसों की कतार देखी जा सकती हैं जबकि फ्रांस में आईसीयू इकाईयां 92 फीसदी तक भर चुकी हैं। स्पेन के बार्सिलोना के आईसीयू में डॉक्टर मरीजों की बढ़ती संख्या से जूझ रहे हैं। आईसीयू कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज का आखिरी मोर्चा है और यूरोप इस मोर्चे पर कमजोर पड़ रहा है क्योंकि यहां बिस्तरों और मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों और नर्सों की कमी हो रही है। कई स्वास्थ्य अधिकारी कड़ी पाबंदियों को लगाने की वकालत कर रहे हैं और आगाह कर रहे हैं कि अगर और बिस्तर जोड़ भी लिए जाएं तो मरीजों के इलाज के लिए प्रशिक्षित डॉक्टरों और नर्सो की कमी है। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ओलिवियर वेरन ने बताया कि फ्रांस में पिछले बसंत मौसम से अब तक 7000 से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मियों ने आईसीयू का प्रशिक्षण हासिल किया था। नर्सिंग छात्रों, इंटर्न और पराचिकित्सकों सभी की सूची तैयार की गई थी। यहां 92.5 फीसदी तक आईसीयू भरे हैं और मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। वही इटली में राष्ट्रीय डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रमुख फिलिपिनो एनेली ने बताया कि मौजूदा संक्रमण दर के हिसाब से जल्द ही ऐसा समय आएगा कि मरीजों के लिए डॉक्टर मौजूद नहीं होंगे।

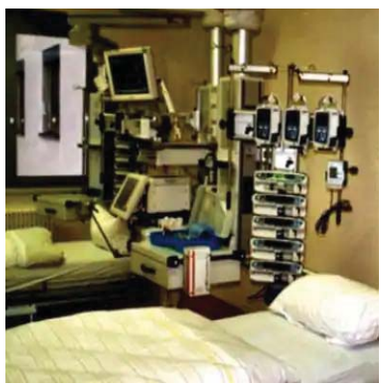

जर्मन बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन के पीछे है शादीशुदा वैज्ञानिक जोड़ा, दोनों को है चिकित्सा रिसर्च का जुनून

नई दिल्ली। जर्मन बायोटेक फर्म में कोविड -19 वैक्सीन पर बायोनटेक और यूएस पार्टनर फाइजर इंक के सकारात्मक डेटा के पीछे एक विवाहित जोड़े की अप्रत्याशित सफलता है। ये वही कपल है जिन्होंने कैंसर के खिलाफ इम्यून सिस्टम के उपयोग के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। फाइजर ने सोमवार को कहा कि एक बड़े अध्ययन में शुरुआती आंकड़ों के आधार पर कोविड -19 को रोकने में इसका प्रयोगात्मक टीका 90% से अधिक प्रभावी रहा है। मेगजीन, वेल्ट एम सोनटैग के अनुसार, बायोनेटेक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोलोन में एक फोर्ड कारखाने में काम करने वाले एक तुर्की आप्रवासी के बेटे उगुर साहिन, 55, उनकी पत्नी ओजेस तुएरेसी, 53 के साथ बोर्ड के सदस्य हैं। नैस्डैक-लिस्टेड बायोएनटेक का बाजार मूल्य, जो कि सह-स्थापित है, एक साल पहले के 4.6 बिलियन डॉलर के मुकाबले शुक्रवार को करीब 21 बिलियन डॉलर तक बढ़ गया, जिसमें कोरोना वायरस के खिलाफ टीके की प्रमुख भूमिका थी। वेंचर कैपिटल फर्म MIG AG के बोर्ड मेंबर मैथियस क्रोमेयर ने कहा, अपनी उपलब्धियों के बावजूद, वह जोड़ा हमेशा विनम्र रहता है। उन्होंने कहा कि साहिन आमतौर पर जींस पहनकर अपने हस्ताक्षर वाली साइकिल हेलमेट और बैकपैक लेकर बिजनेस की बैठकों में पहुंचते हैं। चिकित्सा का अध्ययन करने और एक चिकित्सक बनने के अपने बचपन के सपने का पालन करते हुए, साहिन ने कोलोन और दक्षिण-पश्चिमी शहर होम्बर्ग के अस्पतालों में पढ़ाने का काम किया, जहाँ वे अपने शुरुआती शैक्षणिक जीवन के दौरान तुएरेसी से मिले। चिकित्सा अनुसंधान और ऑन्कोलॉजी उन दोनों का एक साझा जुनून बन गया। तुर्की के एक चिकित्सक की बेटी तुएरेसी ने एक मीडिया साक्षात्कार में कहा था कि उनकी शादी के दिन भी, दोनों ने प्रयोगशाला में काम किया था। साथ में उन्होंने प्रतिरक्षा प्रणाली को कैंसर के खिलाफ लड़ाई में संभावित सहयोगी के रूप में बताया और प्रत्येक ट्यूमर के अद्वितीय आनुवंशिक मेकअप को संबोधित करने की कोशिश की। 2008 में स्थापित, BioNTech ने कैंसर इम्यूनोथेरेपी उपकरणों की एक व्यापक श्रेणी पर काम किया। इसमें mRNA शामिल है, जो एक बहुमुखी संदेशवाहक पदार्थ है जो कोशिकाओं में आनुवंशिक निर्देश भेजता है। BioNTech की कहानी ने एक नया मोड़ तब ले लिया जब जनवरी में साहिन को चीनी शहर वुहान में एक नए वायरस कोरोना के प्रकोप के बारे में जानकारी मिली और वे एंटी-कैंसर mRNA दवाओं से

mRNA- आधारित वायरल टीकों पर काम करने लगे।

भारतीय पोत के फंसे होने से चीन ने किया इनकार, कहा- ऐसी कोई सूचना नहीं

एजेंसी, बीजिंग। चीन ने सोमवार को कहा कि उसे ऑस्ट्रेलिया से कोयला ला रहे चालक दल के 23 सदस्यों वाले किसी भारतीय पोत के पांच महीने से चीनी अपतटीय क्षेत्र में फंसे होने की कोई सूचना नहीं है। भारतीय पोत के जून से हुबेई प्रांत के तांगशान के नजदीक फंसे होने के बारे में सवाल पूछे जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई सूचना नहीं है। उनसे यह भी पूछा गया था कि क्या इसका कोई संबंध चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच खराब संबंधों से है। वेनबिन ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, आपने जिस विशेष स्थिति का उल्लेख किया, मुझे उस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं आपको सलाह देता हूं कि इसके बारे में संबंधित सक्षम प्राधिकार या स्थानीय सरकार से पता करें।

मीडिया में आई खबरों के अनुसार भारतीय पोत 'जग आनंद जून महीने से चालक दल के सदस्यों के साथ चीन के जिंगतांग बंदरगाह पर फंसा है और उसने तत्काल मदद मांगी है। चालक दल के सदस्य ने कहा था कि कोयले से भरा जहाज पीछले पांच महीने चीन के तांगशान के नजदीक बंदरगाह पर फंसा हुआ है। चालक के दल के सदस्यों ने वहां से निकलने के लिए मदद की मांग की थी।

ट्रंप ने अभी घोषित नहीं की है पारी, उधर, सत्ता बदलाव की अपनी योजना पर आगे बढ़े बाइडन

वॉशिंगटन, एजेंसी। एक तरफ नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन देश की बागडोर संभालने की तैयारी कर रहे हैं तो वहीं ट्रंप के प्रचार अभियान की तरफ से कहा गया है कि 2020 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव अभी संपन्न नहीं हुआ है और संकेत दिया कि वह 'सटीक और ईमानदार मतगणना' नजीते हासिल करने के सभी संभावित विकल्पों को टटोलेंगे। निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीन नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनावों में डेमोक्रेट बाइडन से करीबी मुकाबले के बाद हार मानने से इनकार कर दिया और वह परिणाम के लिहाज से अहम रहे कई राज्यों में कानूनी लड़ाई का दबाव बना रहे हैं, लेकिन मतदाताओं को लेकर अनियमितताओं या चुनावों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। इन चुनावों को हालिया अमेरिकी इतिहास में सबसे विभाजक और कड़वाहट भरे राष्ट्रपति चुनाव के तौर पर देखा जा रहा है। राष्ट्रपति का नतीजों को स्वीकार करने से इनकार का मतलब है कि चुनाव संबंधी विवाद हफ्तों चल सकता है क्योंकि राज्य अपने आंकड़ों को प्रमाणित करेंगे या फिर यह दिसंबर के मध्य तक खिंच सकता है जब 538 सदस्यीय इलेक्टोरल कॉलेज को मतदान करना है। राष्ट्रपति ट्रंप बार-बार और निराधार दावे करते रहे हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने चुनाव के नतीजों में गड़बड़ी की

कोशिश की। कुछ अमेरिकी मीडिया के अनुमानों के मुताबिक बाइडन ने कम से कम 290 इलेक्टोरल मत जीते हैं जो 538 इलेक्टोरल कॉलेज मतों में से जीत के लिये जरूरी 270 से 20 ज्यादा हैं। ट्रंप को 214 इलेक्टोरल मत मिले हैं। शनिवार को मीडिया ने चूंकि बाइडन के महत्वपूर्ण राज्य पेन्सिलवेनिया में जीत और व्हाइट हाउस पर दावा करने के लिये पर्याप्त मत हासिल करने का अनुमान व्यक्त किया था, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने सत्ता की बागडोर संभालने की अपनी योजना पर कदम बढ़ाने शुरू कर दिये थे। बाइडन ने सोमवार को कोरोना वायरस पर उन्हें परामर्श देने के लिये एक कार्यबल का गठन किया था। इस महामारी से देश में 2.36 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बाइडन तकनीकी रूप से मौजूदा सरकारी कर्मचारियों के साथ जनवरी के अपने शपथ-ग्रहण से पहले सरकार बनाने की पहल नहीं कर सकते, जब तक ट्रंप द्वारा ऐसा करने की मंजूरी न दी जाए। ट्रंप ने बाइडन से हार नहीं मानी है और सार्वजनिक रूप से हार स्वीकार भी नहीं की है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने सोमवार को मतदाताओं की धोखाधड़ी को लेकर अपुष्ट दावे किए। रिपब्लिकन नेशनल कमेटी की अध्यक्ष रोन्ना मैक्डेनियल के साथ प्रेस सचिव कैली मैकनैनी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ' 'यह चुनाव अभी संपन्न नहीं हुआ है, उससे काफी दूर है। हमनें अभी सटीक, ईमानदार मतगणना नतीजे हासिल करने की प्रक्रिया शुरू की है। हम सभी अमेरिकियों के अधिकार के लिये लड़ रहे हैं जो न सिर्फ इन चुनावों में भरोसा चाहते हैं बल्कि आने वाले कई चुनावों में भी।

' ' ट्रंप के प्रचार अभियान सलाहकार के तौर पर मैकनैनी ने डेमोक्रेटिक पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका में सिर्फ एक दल है जो मतदाता पहचान-पत्र, हस्ताक्षरों के सत्यापन, नागरिकता, आवास प्रमाण-पत्र और अर्हता का विरोध करता है। उन्होंने कहा, ' 'अमेरिका में सिर्फ एक दल है जो मतगणना कक्ष से पर्यवेक्षकों को दूर रखने की कोशिश करता है और मेरे दोस्तों वह डेमोक्रेटिक पार्टी है। आप यह रुख इसलिये नहीं अपनाते क्योंकि आप ईमानदार चुनाव चाहते हैं।

' ' मैक्डेनियल ने संवाददाताओं को बताया कि मिशिगन में पार्टी ने मतदान संबंधी गड़बड़ियों को लेकर दो नई याचिकाएं दायर की हैं। उन्होंने कहा, ' 'यहां तक कि चुनावी गड़बड़ी का एक मामला भी हम सभी के लिए काफी होना चाहिए।'' इस बीच, अमेरिकी अटॉर्नी जनरल विलियम बार्र ने संघीय अभियोजकों को बताया कि उन्हें आने वाले हफ्तों में राज्यों द्वारा नतीजों के प्रमाणन के कदम से पहले चुनावी गड़बड़ियों के आरोपों की जांच करनी चाहिए।

चुनाव में मिली हार के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा मंत्री मार्क एस्पर को पद से हटाया

एजेंसी, वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में मिली हार की गाज रक्षा मंत्री मार्क एस्पर पर गिरी है। ट्रंप ने उन्हें पद से हटा दिया है। ट्रंप ने एक ट्वीट में कहा कि राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी केंद्र के निदेशक क्रिस्टोफर मिलर को तत्काल प्रभाव से अंतरिम रक्षा मंत्री बनाया जाता है। गौरतलब है कि ट्रंप और एस्पर के संबंधों में काफी समय से खटास है। चुनाव में हार के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जनवरी में नए प्रशासन के कार्यकाल सम्भालने पर सत्ता का सहज हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए देश के निर्वाचित राष्ट्रपति जो मबाइडेन की टीम के साथ सहयोग करने का दबाव बढ़ रहा है। जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेटन (जीएसए) पर बाइडेन को निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप से औपचारिक रूप से मान्यता देने की जिम्मेदारी है। इसके बाद सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया आरंभ होगी। एजेंसी की प्रशासक एमिली मर्फी ने अभी तक यह प्रक्रिया आरंभ नहीं की है और न ही यह बताया है कि वह कब ऐसा करेंगी। एमिली की नियुक्ति ट्रंप ने की थी। अभी तक हार स्वीकार न करने वाले और चुनाव में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाले ट्रंप सरकार बनाने की डेमोक्रेटिक पार्टी की कोशिश बाधित कर सकते हैं। बाइडेन के सत्ता हस्तांतरण सहयोगी जेन प्साकी ने रविवार को कहा, अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं उसके आर्थिक हित इस बात पर निर्भर करते हैं कि संघीय सरकार यह स्पष्ट और त्वरित संकेत दे कि वह अमेरिकी लोगों की इच्छा का सम्मान करेगी और सत्ता के शांतिपूर्ण एवं सहज हस्तांतरण में सहयोग करेगी। पिछले तीन कार्यकालों में शामिल रहे एक द्विदलीय समूह ने भी ट्रंप से ' 'चुनाव के बाद सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया तत्काल आगे बढ़ाने की अपील की है। सेंटर फॉर प्रेजिडेंशियल ट्रांजिशन सलाहकार बोर्ड ने एक बयान में कहा कि यह कड़ी मेहनत से लड़ा गया चुनाव था, लेकिन इतिहास ऐसे राष्ट्रपतियों के उदाहरण से भरा पड़ा है, जिन्होंने चुनाव परिणाम के बाद अपने उत्तराधिकारियों की गरिमा के साथ मदद की।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सफलता की सीढ़ी

जनसंपर्क से चढ़ें

जनसंपर्क की दुनिया मे स्थान बनाने के लिए आप संगठन के जनसंपर्क विभाग या पेशेवर फर्म के जनसंपर्क विभाग में शामिल हो सकते हैं, जो ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करता हैक। ऐसी एजेंसियां व्यक्तिगत तौर पर भी कार्य करती हैं। प्रारंभ में व्यक्ति को ट्रेनी के रूप में रखा जाता है। कई ऐसे सरकारी और गैर सरकारी संगठन हैं जो जनसंपर्क अधिकारी के रूप में उम्मीदवार को संस्थान से जोड़ते हैं। इस क्षेत्र में उच्च योग्यता होने के बाद आप शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़ सकते हैं।

सभी को अपने शब्दों पर पूरा विश्वास होता है,अगर ऐसा ही कुछ विश्वास आपको है, तो बेशक एक सफल कैरियर के रूप में चुनें जनसंपर्क का जादुई क्षेत्र आइए जानते हैं कि जनसंपर्क के क्षेत्र में आपके लिए कैसी संभावनाएं हैं। जनसंपर्कचुनौतियों से भरा एक बेहतर कैरियर है। अगर कहा जाए यह किसी की छवि बनाने का कार्य भी होता है। जो मुख्यतः शब्दों को खेल होता है। हम किसी न किसी तरीके से अपने परिवार साथियों तथा सहकर्मियों के साथ जनसंपर्क के नियम लागू करते हैं।

जनसंपर्क आखिर है क्या?

व्यावसायिक दृष्टि से जनसंपर्क (पब्लिक रिलेशन) प्रबंधन का ऐसा साधन है जिससे कॉर्पोरेट संगठन सरकार तथा कुछ सीमा तक व्यक्ति की छवि बनाने में सहायक मिलती है। अब तो राज्य सरकारों ने भी जनमानस पर अनुकूल छाप छोड़ने के लिए जनसंपर्क कार्यों को महत्व देना शुरू कर दिया है। जनसंपर्क के माध्यम से संगठन सभी से संपर्क बनाए रख सकता है। इस वर्ग में ऐसे लोग सेवाओं का लाभ उठाते हैं या जो संगठन में निवेश करते हैं और यहां तक कि इस वर्ग में उस संगठन के कर्मचारी भी हो सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन के दौर ने जनसंपर्क का क्षेत्र ओर अधिक व्यापक बना दिया है। आज जीवन के हर क्षेत्र में जनसंपर्क को महत्व दिया जाने लगा है। इस कार्य क्षेत्र में कंपनी से लेकर उत्पाद जनता परियोजना या विचारों तक सब कुछ शामिल हैं। लोकप्रिय छवि बनाने केअलावा जनसंपर्क संगठन और इसके काम को सही आकार व्यवहार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

क्या हो आपकी खासियत?

परिस्थिति कैसी भी हो कंपनी कोई भी फैसला लेने से पहले जनसंपर्क विभाग से सलाह और सेवाएं जरूर लेती हैं, इसलिए जनसंपर्क कार्य से जुड़ व्यक्ति के पास दबाव के समय भी सही फैसले लेने की क्षमता आवश्यक सूचना हासिल करने तथा व्यावहारिक एंव प्राभावी हल ढूंढ निकालने की दक्षता होनी चाहिए। इसक अलावा वर्तमान समस्याओं को सुलझाने की कल्पना शक्ति तथा समस्याओं को सुलझाने केअनुसार अपने को ढालना लोगों तथा समूह के साथ आमने सामने संपर्क स्थापित करने के लिए लेखन क्षमता आत्मविश्वास सही तरीके से बात को रखना अन्य लोगों के प्रति सम्मान कूटनीति जैसे गुण होना आवश्यक है, जिसके चलते ही आप इस क्षेत्र में सफल हो पाएंगे।

बेहतर सैलरी

इस क्षेत्र में जितनी जॉब की अधिकता है, उतनी ही अच्छी सैलरी भी है। जो आपकी योग्यता और काम पर निर्भर करता है। जनसंपर्क प्रशिक्षणार्थी का प्रारंभ में वेतन 5000 रूपए से 7000 रूपए के बीच प्रतिमाह होता है, लेकिन यह कंकपनी और उम्मीदवार के ऊपर निर्भर करता है कि वेतन का स्वरूप कैसा होगा। एक बार अनुभव हो जाने के बाद आप 12000 रूपए से 25000 हजार रूपए तक के बीच कहीं भी, किसी भी संगठन में वेतन पा सकते हैं। वैसे इंटरनेशनल कपंनियों तथा कॉर्पोरेट सेक्टर में वेतन अन्य संगठन के मुताबिक ज्यादा है।

जॉब की संभावनाएं

यह क्षेत्र जॉब और सैलरी दोनों के लिए ही बेहतर है। जनसंपर्क की दुनिया मे स्थान बनाने के लिए आप संगठन के जनसंपर्क विभाग या पेशेवर फर्म के जनसंपर्क विभाग में शामिल हो सकते हैं, जो ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करता हैक। ऐसी एजेंसियां व्यक्तिगत तौर पर भी कार्य करती हैं। प्रारंभ में व्यक्ति को ट्रेनी के रूप में रखा जाता है। कई ऐसे सरकारी और गैर सरकारी संगठन हैं जो जनसंपर्क अधिकारी के रूप में उम्मीदवार को संस्थान से जोड़ते हैं। इस क्षेत्र में उच्च योग्यता होने के बाद आप शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़ सकते हैं।

आवश्यक योग्तया

इस क्षेत्र मे डिग्री से अधिक आपकी पर्सनल स्किल्स महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रवेश पाने के लिए आपके पास प्रोफेशनल डिग्री को होना भी जरूरी है। जनसंपर्क अधिकारी के लिए किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होना आवश्यक है। वेसे इस क्षेत्र की बढ़ते क्रेज को देखते हुए अनेक संस्थान जनसंपर्क से संबंधित पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा पाठ्यक्रम में पत्रकारिता विज्ञापन या जनसंचार भी शामिल हैं। इसके अलावा अब कंप्यूटर की जानकारी को महत्व दिया जा रहा है।

स्टाइल से कैरी करें

लैपटॉप

नए जमाने के युवाओं के कंधे से कंधा मिलाने के लिए इस अल्ट्रा स्टालिश उत्पाद की लेटेस्ट लाइन लॉन्च की गई है जो न सिर्फ सुविधाओं से लैस है, बल्कि अपना स्टाइल बढ़ाने और एक फैशन एसेसरी के तौर पर भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। यह नया कलेक्शन आपके लैपटॉप और लैपटॉप एसेसरीज की मौसम और खरोंचों से सुरक्षा भी करेगा और वह भी स्टाइल के साथ।

डिजिटल लाइफस्टाइल की आदी हो चुकी इस जनरेशन को अपने लैपटॉप सॉफ्ट गुड्स की मदद से स्टाइलिश बनाने का बीड़ा उठाया है बेल्किन ने।

बेल्किन ने फैशन डिजाइनर और बॉलीवुड के स्टाइल गुरु रॉकी एस के साथ मिलकर अपने ट्रेंडी और स्टाइलिश लैपटॉप बैग्स और स्लीव्स की लेटेस्ट श्रृंखला लॉन्च की। रॉकी एस और मॉडल्स ने बेल्किन के शानदार लैपटॉप बैग और स्लीव्स का नया स्टाइल रैंप पर दिखाया।

नए जमाने के युवाओं के कंधे से कंधा मिलाने के लिए इस अल्ट्रा स्टालिश उत्पाद की लेटेस्ट लाइन लॉन्च की गई है जो न सिर्फ सुविधाओं से लैस है, बल्कि अपना स्टाइल बढ़ाने और एक फैशन एसेसरी के तौर पर भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। यह नया कलेक्शन आपके लैपटॉप और लैपटॉप एसेसरीज की मौसम और खरोंचों से सुरक्षा भी करेगा और वह भी स्टाइल के साथ।

फिर चाहे यह 360 डिग्री ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम वाले टॉप, लोअर और मेसेंजर बैग हों या अतिरिक्त शोल्डर स्ट्रैप वाले बैकपैक हों या फिर ईजी एक्सेस पॉकेट और सुरक्षा के लिहाज से परफेक्ट स्लिम प्रोफाइल नेट बुक स्लीव उपलब्ध हो जिसे अलग से भी उपयोग में लाया जा सकता है या अपने सूटकेस में भी रखा जा सकता है। बेल्किन के पास आधुनिक उपभोक्ता की स्टोरेज जरूरतों के हिसाब से स्टाइलिश बिजनेस कैजुअल सोल्यूशन भी मौजूद हैं।

प्रोफेशनल छात्रों और अन्य ऐसे उपभोक्ता जो जो अपने लैपटॉप बैग को कई कामों के लिए और फैशन एसेसरी की तरह उपयोग करते हैं, उन्हें बेल्किन की यह नई लाइन दोस्तों और प्रोफेशनल्स के बीच नया स्टाइल आइकन बनने में मदद करेगी।

इस बारे में बेल्किन इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहित आनंद ने कहा, ट्आज के युवा लैपटॉप बैग को सिर्फ अपने लैपटॉप रखने के झोले की तरह उपयोग नहीं करते, बल्कि उसे स्मार्ट हैंडबैग, फैशन एसेसरी और मल्टी परपस बैग की तरह काम में लाते हैं। हमारी यह नई लाइन इनके फैशन और स्टाइल स्टमेंट के साथ अच्छी तरह ताल-मेल बिठाएगी। और जब फैशन गुरु रॉकी एस का साथ भी हमारे उत्पाद को मिला तो जाहिर है कि हमारी यह नई श्रृंखला युवाओं के बीच ट्रेंड सेट करने में मददगार साबित होगी।

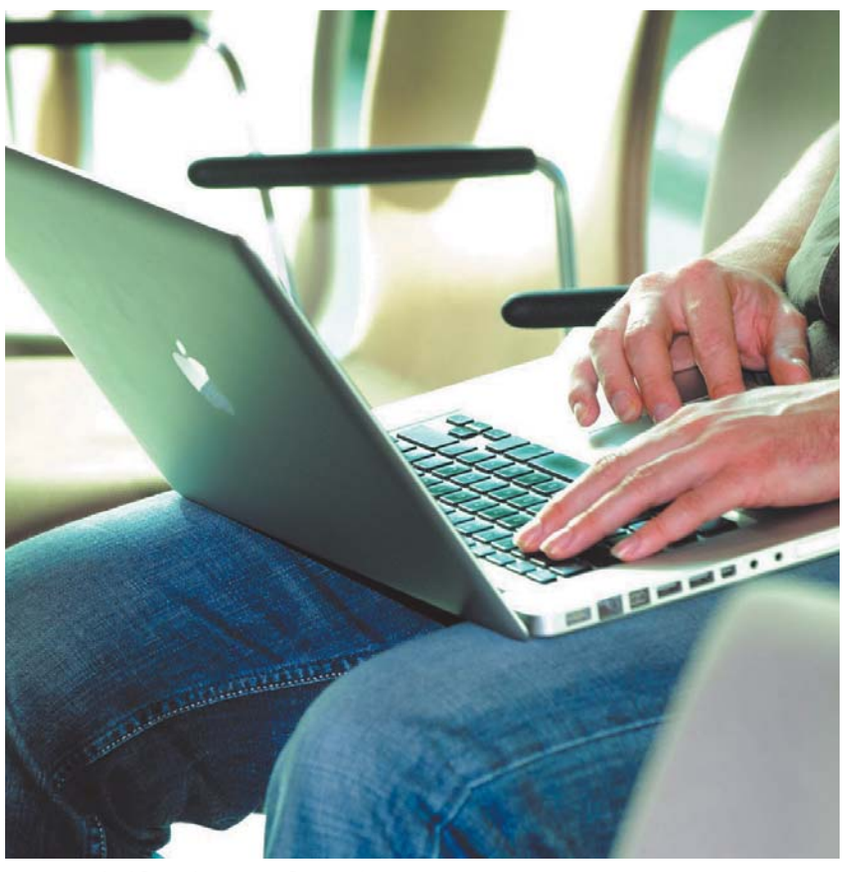

पर्वतारोहण
में ऊंचाई छूता कैरियर

इस क्षेत्र में कैरियर बनाने हेतु स्वस्थ शरीर पहली आवश्यककता है। इसके साथ ही इसमें सजगता सूझबूझ विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना होता है। पर्वतारोहण में उचित प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आप सार्वजनिक या निजी विभाग में अपनी योग्यता के अनुसार कार्य संभाल सकते हैं।

पर्वतारोहण के क्षेत्र में कैरियर की बहुत उजली संभावनाएं हैं। पर्वतारोहण के क्षेत्र में कैरियर बनाने हेतु किसी खास योग्यता की आवश्यकता नहीं है जबकि साहसी होना आवश्यकता है। इस क्षेत्र में कैरियर बनाने हेतु स्वस्थ शरीर पहली आवश्यककता है। इसके साथ ही इसमें सजगता सूझबूझ विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना होता है। पर्वतरोहण में उचित प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आप सार्वजनिक या निजी विभाग में अपनी योग्यता के अनुसार कार्य संभाल सकते हैं।

पर्वतारोहण का कोर्स कराने वाले देश के प्रमुख संस्थान हैं।

हिमाचल पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग
पर्वतारोहण निदेशालय, मनाली
एडवेंचर एकेडमी ऑफ राजस्थान जयपुर
जवाहर पर्वतारोहण एवं शीत क्रीड़ा संस्थान, पहलगाम
इंडियन स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर

पर्वतारोहण के क्षेत्र में आप चाहें तो प्रशिक्षण संस्थान भी खेलकर अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं।

पर्वतारोहण के लिए प्रशिक्षण जरूरी

पर्वतारोहण एक चुनौती एक साहस और आपको बुलंद सोच का नतीजा है, जिसमें आपका आत्मविश्वास उस लंबी पैदल यात्रा को सहज बनाने का काम करती है, क्योंकि इस चढ़ाई में न तो आपको कोई शिविर मिलेंगे और न ही लंगर। आमतौर पर बेदर्द मौसम और एक रहस्य मयी ऊंचाई और हर कोने में और हर कदम पर खतरे की सुगबुगाहट आपको दहला देती है। ऐसे मे आपको इन परिस्थियों से सिर्फ एक चीज सह ही बचा सकती है, वो आपका पूर्व प्रशिक्षण आपके अभियान की सफलता के लिए है।

कुछ आवश्यक वस्तुएं

शीतकालीन ऊपर का कपड़ा
चढ़ाई गियर हारनेसेस या घुस
हेलमेट, रस्सियां
ट्रेकिंग युक्त जूते
शीतकालीन बैकपेकिंग टेंट
अनुदेशात्मक किताबें और मानचित्र

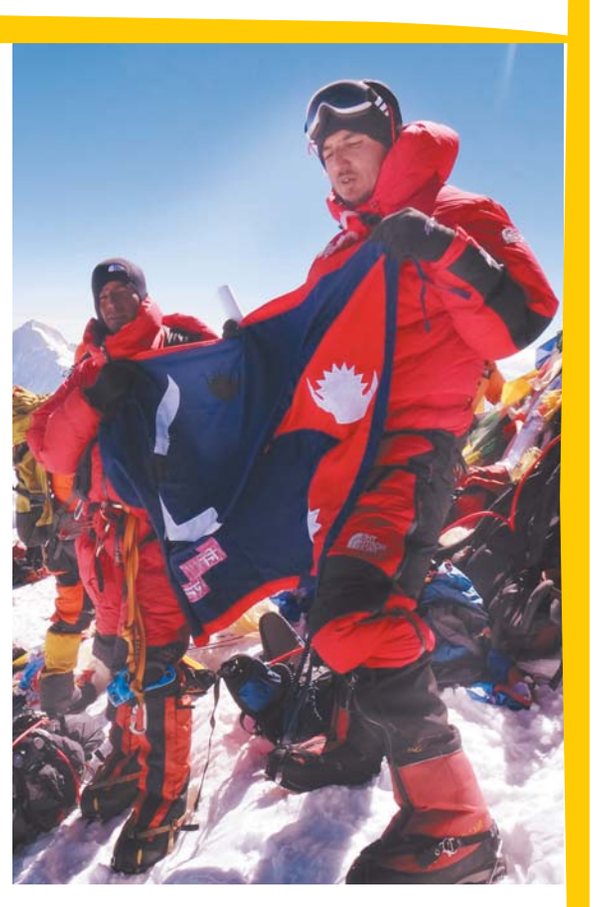

इन्हें भी ध्यान रखें

आपका बड़ी चट्टानों बर्फ रात में विविध तरह के इलाके पर रहने चलने का अभ्यास।
अलास्का की डेनालीर पर बसंत में अपनी पहली चढ़ाई करें।
एक जोरदार और नियमित प्रशिक्षण और पर्वतारोहण।
पहाड़ों पर अक्सर जाएं।
भोगोलिक और अनुभवयुक्त पुस्तकों को पढ़ें। सबसे अच्छा उपकरण का प्रयोग करें, क्योंकि आपकी जिंदगी उस पर निर्भर है।
विशेषज्ञों से सलाह लें।

क्रांति समय

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

कर्नाटक उपचुनाव : आरआर नगर सीट से भाजपा उम्मीदवार एन मुनिरत्न जीते

बेंगलुरु। कर्नाटक में राजराजेश्वरी नगर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी एन मुनिरत्न ने मंगलवार को जीत हासिल की। अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल भाजपा में शामिल होने वाले मुनिरत्न ने अपने निकटम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस प्रत्याशी कुसुमा एच को 57,000 से ज्यादा वोटो से शिकस्त दी। जद (एस) इस सीट पर तीसरे स्थान पर रही। आरआर नगर सीट पर तत्कालीन कांग्रेस विधायक मुनिरत्न को दल-बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराए जाने की वजह से उपचुनाव कराया गया है। मुनिरत्न की यह 2013 से लगातार तीसरी जीत है। वह पहली बार भाजपा के टिकट पर विधायक निर्वाचित हुए हैं।

मध्य प्रदेश की स्थिति पर बोले दिग्विजय सिंह, लोकतंत्र हार गया, नोटतंत्र जीत गया

भोपाल। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मंगलवार को हो रही वोटों की गिनती में सत्तारुढ़ भाजपा 19 सीटों पर, कांग्रेस सात सीटों पर और बसपा एक सीट पर आगे हैं। जबकि भाजपा का एक उम्मीदवार जीत चुका है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल खड़ा किया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र और नोटतंत्र के बीच में है। जनता और प्रशासन के बीच में हैं। आज लोकतंत्र हार गया। आज क्या कारण है कोई भी विकसित देश ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करता है।

वहीं, मतगणना से पहले दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर जीत का भरोसा जताया था लेकिन नतीजे ठीक उसके उलट निकले। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि मतदान भी मंगलवार को हुआ और मतगणना भी मंगलवार को है। मुझे विश्वास है हनुमान जी अपने परम भक्त कमलनाथ को निराश नहीं करेंगे। कमलनाथ के साथ अन्याय हुआ है न्याय मिलेगा। भगवान के घर देर है। अंधेर नहीं है। बोलो- सिया पति रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय।

जेएनयू परिसर में स्वामी विवेकानंद की आदमकद मूर्ति का अनावरण करेंगे पीएम मोदी

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को राजधानी दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के परिसर में स्वामी विवेकानंद की आदमकद मूर्ति का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से होने वाले इस अनावरण कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी उपस्थित रहेंगे। बयान में कहा गया कि स्वामी विवेकानंद के सिद्धांत और संदेश आज भी देश के युवाओं को राह दिखाते हैं और भारत को गर्व है कि यहां पैदा हुई उनकी जैसी महान शख्सियत आज भी दुनिया भर के करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। बयान के मुताबिक, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद के आदर्श जितने उनके जीवनकाल में प्रासंगिक थे वह आज भी हैं। प्रधानमंत्री ने हमेशा जोर दिया है कि लोगों की सेवा करने और युवाओं को सशक्त बनाने से देश शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनता है और इससे देश की वैश्विक साख भी बढ़ती है। भारत की समृद्धि और शक्ति यहां के लोगों में निहित है और सभी को सशक्त करने से ही देश आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल कर सकेगा।

नोटबंदी पर जश्न मनाना पीड़ितों की कब्र पर केक काटने जैसा : शिवसेना

मुंबई। शिवसेना ने मंगलवार को भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि नोटबंदी की चौथी सालगिरह मनाना उन लोगों की कब्रों पर केक काटने के समान है जो इसकी वजह से 'बर्बाद' हुए और जिनमें से कइयों ने 'आत्महत्या' तक कर ली थी। शिवसेना ने अपने मुखपत्र 'सामना' में प्रकाशित संपादकीय में वर्ष 2016 के नोटबंदी के फैसले को भारत के इतिहास का 'काला अध्याय' करार दिया। पार्टी ने दावा किया कि नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने से देश के हितों को नुकसान हुआ।

सामना ने लिखा, ''फैसले (नोटबंदी के) पर जश्न मनाना, जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हुई...नौकरियां चली गई...आत्महत्याएं की गई और कारोबार एवं उद्योग तबाह हो गए , वैसा ही है जैसे ऐसे लोगों की कब्रों पर जन्मदिन का केक काटना।'' उल्लेखनीय है कि आठ नवंबर 2016 को 500 और 1000 रूपये मूल्य के पुराने नोटों को बंद करने के फैसले की चौथी सालगिरह परप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि इससे कालाधन कम करने और पारदर्शिता लाने में मदद मिली।

भारत में 24 घंटे में सामने आए 38 हजार से अधिक मामले, 448 और लोगों की मौत

नयी दिल्ली। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 38,073 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 85,91,730 हो गए। वहीं 79,59,406 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के साथ ही मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 92.64 प्रतिशत हो गई है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह आठ बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 448 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,27,059 हो गई है। देश में कोविड-19 से मृत्यु दर 1.48 प्रतिशत है।

एससीओ सम्मेलन में पीएम मोदी ने चीन और पाक को दिया क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने का संदेश

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

चीन और पाकिस्तान को दिए गए सख्त संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सभी सदस्य राष्ट्रों को एक-दूसरे की सार्वभौमिकता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। प्रधानमंत्री का यह बयान पूर्वी लद्दाख में पिछले दिनों भारत और चीन के बीच सीमा पर हुए हिंसक गतिरोध और कश्मीर मुद्दे के अंतरराष्ट्रीयकरण के पाकिस्तान के प्रयासों तथा सीमापार से भारत के खिलाफ उसके द्वारा चलाई जा रही आतंकवादी गतिविधियों की पृष्ठभूमि में आठ देशों वाले एससीओ शिखर सममेलन में आया।

वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मोदी ने इस शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान भी इसमें मौजूद थे। सम्मेलन की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन कर रहे थे। सदस्य राष्ट्रों के बीच संपर्क मजबूत करने में भारत की सहभागिता का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा, ''भारत का मानना है कि कनेक्टिविटी को और अधिक गहरा करने के लिए यह आवश्यक है कि एक-दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को सम्मान देते हुए मूल सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ा जाए।''

मोदी ने अपने संबोधन में एससीओ के एजेंडे में द्विपक्षीय मुद्दों को लाने के प्रयासों को ''दुर्भाग्यपूर्ण'' करार दिया और कहा कि भारत एससीओ चार्टर में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र का मूल लक्ष्य अभी अधूरा है और कोविड-19 महामारी की आर्थिक तथा सामाजिक पीड़ा से जूझ रहे विश्व को उसकी व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन की अपेक्षा है। उन्होंने कहा, ''संयुक्त राष्ट्र ने अपने 75 वर्ष पूरे किए हैं। लेकिन अनेक सफलताओं के बाद भी संयुक्त राष्ट्र का मूल लक्ष्य अभी अधूरा है। महामारी की आर्थिक और सामाजिक पीड़ा से जूझ रहे विश्व की अपेक्षा है कि संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन आए।''

उन्होंने आज की वैश्विक वास्तविकताओं को दर्शाने वाले और सभी हितधारकों की अपेक्षाओं, समकालीन चुनौतियों तथा मानव कल्याण जैसे विषयों पर चर्चा के लिए ''बहुपक्षवाद'' की आवश्यकता पर बल दिया और उम्मीद जताई कि इस प्रयास में एससीओ के सदस्य राष्ट्रों का पूर्ण समर्थन मिलेगा। मोदी ने कहा कि भारत का शांति, सुरक्षा और समृद्धि पर दृढ़ विश्वास है और उसने हमेशा आतंकवाद, अवैध हथियारों की तस्करी, मादक द्रव्य और धन शोधन के विरोध में आवाज उठाई है।

उन्होंने कहा, ''भारत एससीओ चार्टर में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, एससीओ के तहत काम करने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहा है परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसके एजेंडे में बार-बार, अनावश्यक रूप से,द्विपक्षीय मुद्दों

को लाने के प्रयास हो रहे हैं। यह एससीओ चार्टर और 'शंघाई भावना' का उल्लंघन करते हैं। इस तरह के प्रयास एससीओ को परिभाषित करने वाली सर्वसम्मति और सहयोग की भावना के विपरीत हैं।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि अभूतपूर्व महामारी के इस अत्यंत कठिन समय में भी भारत के फार्मा उद्योग ने 150 से अधिक देशों को आवश्यक दवाएं भेजी हैं। उन्होंने भरोसा दिया कि दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के रूप में भारत अपनी वैक्सीन उत्पादन और वितरण क्षमता का उपयोग इस संकट से लड़ने में पूरी मानवता की मदद करने के लिए करेगा।

जनरल रावत का बयान, कहा-अगर भारत के पास सैन्य बल नहीं हो तो विरोधी इसका फायदा उठा सकते हैं

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत ने मंगलवार को कहा कि भारतीय सैन्य बल बहुत जटिल और अनिश्चित माहौल में काम कर रहे हैं और उन्हें क्षेत्र में शांति के लिए क्षमता बढ़ानी होगी क्योंकि अगर सैन्य ताकत मजबूत नहीं होगी तो भारत के विरोधी इसका फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत जरूरत पड़ने पर आस पड़ोस में मित्र देशों के साथ अपनी सैन्य क्षमता को साझा करना चाहता है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष रक्षा और सैन्य मुद्दों पर आधारित एक पोर्टल 'भारतशक्ति डॉट इन' के पांचवें वार्षिक सम्मेलन के शुरुआती सत्र को संबोधित कर रहे थे।

जनरल रावत ने कहा, ''आज हम बेहद जटिल, अनिश्चित और अस्थिर माहौल में काम कर रहे हैं। विश्व के तकरीबन हर क्षेत्र में छोटी, बड़ी जंग छिड़ी हुई है। इसलिए यदि हमें खुद की रक्षा करनी है, अपने देश की, अपने देश की अखंडता और अपने लोगों की रक्षा करनी है तो हमें मजबूत सैन्य बल की जरूरत है।'' उन्होंने कहा, ''लेकिन तब

क्या हम कह रहे हैं कि सैन्य बल को युद्ध की तैयारी करनी चाहिए ? नहीं। सैन्य बलों को क्षेत्र में शांति लाने के लिए क्षमता विकसित करनी चाहिए। अगर हमारे पास मजबूत सैन्य बल नहीं होंगे तो विरोधी हमारा फायदा उठाएंगे।''

जनरल रावत का यह बयान महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच पिछले छह महीने से गतिरोध चल रहा है। दोनों पक्षों के बीच गतिरोध सुलझाने के लिए सिलसिलेवार राजनयिक और सैन्य वार्ता भी हुई है। हालांकि कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। सम्मेलन में एक संदेश पढ़ा गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधुनिक उपकरण और नयी प्रौद्योगिकी हासिल करने तथा सैन्य बलों के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा की गईं कई सुधार कवायदों का जिक्र किया गया। संदेश में मोदी ने कहा, ''हम आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए देश के सामूहिक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। '' अपने संबोधन में जनरल रावत ने जंगलों, घाटियों और 6,000 से 6,500 मीटर की ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों जैसे कठिन माहौल में सैन्य बलों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों का जिक्र किया।

जनरल रावत ने कहा, ''हमारी नौसेना हिंद-प्रशांत क्षेत्र में तैनात है, जहां से जहाजों का सबसे ज्यादा आवागमन होता है। उन्हें समुद्र में ही नहीं, बल्कि समुद्र के भीतर काम करने के साथ ही तेजी से बन रहे जटिल हालात के बीच प्रौद्योगिकी को विकसित करने की जरूरत है।'' जनरल रावत ने कहा, ''हम विदेशी भागीदारी को आमंत्रित करने से नहीं हिचकिचाते हैं, जो कि हमारे उद्योगों की सहायता कर सकती है और इससे आगे बढ़ने में मदद मिलती है। हम दुनिया के दूसरे सैन्य बलों खासकर पड़ोसियों के साथ भी अपनी क्षमता साझा करना चाहता है। ''

अलग-अलग देशों के रक्षा अधिकारियों की मौजूदगी में जनरल रावत ने कहा, ''हम उन सबकी मदद करना चाहते हैं जिन्हें हमारे सहयोग की जरूरत है खासकर उन देशों को जो कठिन समय से गुजर रहे हैं और अच्छी हथियार प्रणाली चाहते हैं।'' वायु सेना प्रमुख आर के एस भदौरिया ने कहा कि भारत के विरोधियों से खतरा'गहरा और दीर्घकालिक' है।

राजस्व घाटे की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने 14 राज्यों को जारी किए 6,195 करोड़ रुपए

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

केंद्र सरकार ने 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान की मासिक किस्त के तौर पर 6,195 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह अनुदान 15वें वित्त आयोग की अंतरिम सिफारिशों पर आधारित है जो राज्यों को केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के भुगतान के बाद होने वाले राजस्व घाटे के लिए दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा, ''15वें वित्त आयोग की अंतरिम सिफारिशों के आधार पर 14 राज्यों को 6,195.08 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया है। केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी के भुगतान के बाद राजस्व घाटा अनुदान विभाग ने बराबर की आठ मासिक किस्तों के तहत यह राशि जारी की है।''

अनुदान का लाभ पाने राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर,मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इतनी ही राशि का अनुदान चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-अक्टूबर अवधि में जारी किया गया था। वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी के बाद राज्यों के राजस्व घाटे की केंद्र की ओर पूर्ति के लिए अनुदान की यह व्यवस्था बनायी है।

राजस्थान : चार निगमों में कांग्रेस के महापौर, दो में भाजपा की बल्ले-बल्ले

जयपुर। (एजेंसी)।

राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित तीन प्रमुख शहरों में छह नगर निगमों के महापौर का चुनाव मंगलवार को हुआ। सत्तारूढ़ कांग्रेस चार निगमों में अपने महापौर बनाने में सफल रही है जबकि दो निगमों में भाजपा के उम्मीदवार जीते।

राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार राजधानी जयपुर के जयपुर ग्रेटर नगर निगम में भाजपा की सौम्या गुर्जर ने कांग्रेस की दिव्या सिंह को हराया जबकि जयपुर हेरिटेज नगर निगम में कांग्रेस की मुनेश गुर्जर जीतीं। यहां भाजपा की कुसुम यादव दूसरे स्थान पर रहीं। इसी तरह जोधपुर शहर के जोधपुर उत्तर नगर निगम में कांग्रेस की कुंती परिहार महापौर चुनी गयी हैं। यहां भाजपा की संगीता सोलंकी दूसरे स्थान पर रहीं। जोधपुर दक्षिण में भाजपा की वनिता सेठ महापौर बनी हैं। यहां कांग्रेस की पूजा पारीक दूसरे स्थान पर रहीं। कोटा उत्तर

नगर निगम के महामौर चुनाव में कांग्रेस की मंजू मेहरा ने बाजी मारीं। उन्होंने भाजपा की संतोष बैरवा को हराया। वहीं कोटा दक्षिण नगर निगम में कांग्रेस के राजीव अग्रवाल ने भाजपा के विवेक राजवंशी को हराया। उल्लेखनीय है कि राज्य के नवगठित नगर जयपुर हैरिटेज, जयपुर ग्रेटर, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण में कुल 560 वार्डों के लिए हाल ही चुनाव हुआ। कांग्रेस को जोधपुर उत्तर व कोटा उत्तर नगर निगम में स्पष्ट बहुमत मिला, वहीं भाजपा जयपुर ग्रेटर और जोधपुर-दक्षिण नगर निगम में बहुमत हासिल कर पाई हैं। कोटा दक्षिण तथा जयपुर हेरिटेज में महापौर बनाने में निर्दलीय पार्षदों की बड़ी भूमिका रही। इन सभी नगर निगमों में उप महापौर का चुनाव 11 नवंबर को होगा।

कोटा में महापौर के चुनाव के दौरान भाजपा व कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के अनुसार कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठी चलाई गयी। उन्होंने ट्वीट किया कि कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओ व पत्रकारों पर पुलिस लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि पुलिस के आला अधिकारी इस मामले में ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे।

ईवीएम पर कांग्रेस का मतभेद सामने आया, उदित राज और कार्ति चिदंबरम ने दिया अलग-अलग बयान

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

बिहार विधानसभा चुनाव के रुझानों में महागठबंधन के पिछड़ने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता उदित राज ने मंगलवार को इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब उपग्रह को नियंत्रित किया जा सकता है तो फिर ईवीएम हैक क्यों नहीं की जा सकती। दूसरी तरफ, कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने उदित राज का नाम लिए बगैर कहा कि जब उपग्रह को नियंत्रित किया जा सकता है तो फिर ईवीएम हैक क्यों नहीं की जा सकती ?'' कांग्रेस नेता ने यह सवाल भी किया, ''अमेरिका में अगर ईवीएम से चुनाव होता तो क्या डोनाल्ड ट्रम्प हार सकते थे ?'' बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को चल रही मतगणना के रुझानों के अनुसार दोपहर के समय तक 243 सीटों में से राजग 126 सीटों पर आगे चल रहा है और गठबंधन में भाजपा अपनी सहयोगी पार्टी नीतीश कुमार नीत जद (यू) से बेहतर प्रदर्शन करती दिख रही है।

भारत निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, विपक्षी महागठबंधन 103 सीटों पर बढ़त बनाये हुए है। कांग्रेस सांसद कार्ति ने ट्वीट किया, ''नतीजा चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया जाना बंद होना चाहिए। मेरे अनुभव के मुताबिक, ईवीएम की व्यवस्था मजबूत, उचित और भरोसेमंद है। यह राय मेरी हमेशा से रही है।'' उन्होंने कहा, ''राजनीतिक दलों की ओर से ईवीएम पर सवाल खड़े किए जाते हैं और खासकर चुनाव परिणाम के अपने अनुकूल नहीं होने पर ऐसा होता है। अब तक इस दावे को वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं किया जा सका है।

ईवीएम पर उठ रहे सवालों पर बोला चुनाव आयोग, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती

पटना। (एजेंसी)।

ईवीएम की विश्वसनीयता के संबंध में कुछ नेताओं द्वारा सवाल उठाए जाने के बीच चुनाव आयोग ने मंगलवार को इस बात पर जोर दिया कि यह मशीन पूरी तरह मजबूत है और इससे कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। बिहार विधानसभा चुनाव के रुझानों में महागठबंधन के पिछड़ने के बाद कांग्रेस नेता उदित राज ने मंगलवार को इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब उपग्रह को धरती से नियंत्रित किया जा सकता है तो फिर ईवीएम हैक क्यों नहीं की जा सकती?

दूसरी तरफ, कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने उदित राज का नाम लिए बगैर कहा कि ईवीएम पर सवाल खड़े करने का सिलसिला बंद होना चाहिए क्योंकि इसके साथ छेड़छाड़ का दावा अब तक वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं हो सका है। कांग्रेस सांसद कार्ति ने ट्वीट किया, ''नतीजा चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया जाना बंद होना चाहिए। मेरे अनुभव के मुताबिक, ईवीएम की व्यवस्था मजबूत, उचित और भरोसेमंद है। यह राय मेरी हमेशा से रही है।''

उन्होंने कहा, ''राजनीतिक दलों की ओर से ईवीएम पर सवाल खड़े किए जाते हैं और खासकर चुनाव परिणाम के अपने अनुकूल नहीं होने पर ऐसा होता है। अब तक इस दावे को वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं किया जा सका है।'' ईवीएम के प्रभारी उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन ने मशीन की विश्वसनीयता के संबंध में कुछ नेताओं द्वारा खड़े किए गए सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मशीन पूरी तरह मजबूत है और इससे कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती।

उन्होंने कहा कि बार-बार स्पष्ट किया गया है और फिर से बता दें कि ईवीएम पूरी तरह मजबूत है और इससे छेड़छाड़ नहीं हो सकती। यहां तक कि उच्चतम न्यायालय ने कई बार इस उपकरण के इस्तेमाल को सही बताया है। जैन ने याद दिलाया कि वर्ष 2017 में आयोग ने राजनीतिक दलों को ईवीएम चुनौती दी थी। उन्होंने कहा, ईवीएम की विश्वसनीयता किसी भी संदेह से परे है। इससे अधिक कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकते।

स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशक : सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर, सिद्धिविनायक मंदीर के पास , (भाटेना) हो.सो अंजना सुरत
गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक :सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/751000 (Subject to Surat jurisdiction)